दमण से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

Asli Azadi Dainik @AsliAzadiDainik

asliazadidainikofficial

असली आज़ादी

■ वर्ष: 21, अंक: 231 ■ दमण, बुधवार 03, जून 2026 ■ पृष्ठ: 8 ■ मूल्य: 2 रु ■ RNI NO-DDHIN/2005/16215 ■ संपादक- विजय जगदीशचंद्र भट्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दमण आगमन पर स्वागत के लिए संघ प्रदेश थ्रीडी भाजपा, जनप्रतिनिधि और जनता में भारी उत्साह

जनप्रतिनिधियों और भाजपाईयों का जगह-जगह जनसंवाद और निमंत्रण कार्यक्रमों, विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान के साथ पीएम मोदी के आगमन को लेकर दमण में तैयारियां जोरों पर

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 02 जून। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव की राजधानी दमण में पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस छोटे से संघ प्रदेश में 8वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दमण में नये एयरपोर्ट, नये सरकारी अस्पताल सहित अनेक प्रोजेक्टों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ नमो पथ और राम सेतु को जोडने वाले सिग्नेचर ब्रिज, कन्वेंशन सेंटर सहित अनेक प्रोजेक्टों का भूमिपूजन भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दमण आगमन को लेकर संघ प्रदेश थ्रीडी भाजपा, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक अग्रणियों एवं आम जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दमण आगमन के उपलक्ष्य में दमण में जगह-जगह सफाई अभियान चल रहा है। आज इसी क्रम में नमो पथ के पास भाजपा के प्रभारी दुष्यंत पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेश आगरिया और भाजपा महामंत्री जिग्नेश पटेल के साथ भाजपा पदाधिकारियों एवं भाजपा जनप्रतिनिधियों ने बडे पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर भाजपा नेता विशाल टंडेल, दमण जिला भाजपा अध्यक्ष भरत पटेल, डीएमसी के काउंसिलरों, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों एवं युवाओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने नाइट मार्केट की हर दुकान पर पहुंचकर व्यापारियों एवं नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी के 5 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र भी दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीधे मार्गदर्शन में प्रशासक प्रफुल पटेल ने पिछले 10 सालों में पूरे संघ प्रदेश की सूरत बदल दी है। खासकर दमण की बात करें तो दमण को ऐसी-ऐसी सौगाते मिली है जो न कभी किसी ने सोची थी। 5 जून को फिर एक बार दमण को पर्यटन, कनेक्टीविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सौगाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी जाने वाली है। इसको लेकर अभी से ही पूरे दमण में उत्सव का माहौल है।

पीएम मोदी की दमण यात्रा को लेकर पूर्व सांसद लालू पटेल ने परियारी, मगरवाडा, दमणवाडा और पटलारा में जनता के साथ किया जनसंवाद

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे छोटे से संघ प्रदेश को बडी-बडी सौगाते दी है, 5 जून को दमण को और सौगाते मिलने जा रही है, हम सबको एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और स्वागत करना है: पूर्व सांसद लालू पटेल

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 02 जून। 5 जून को पीएम मोदी के दमण दौरे को लेकर उनके भव्य स्वागत और अभिवादन करने के लिए बडी संख्या में दमणवासियों को उपस्थित रहने के लिए गांव-गांव भाजपाईयों द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है। पूर्व सांसद लालू पटेल ने मोटी दमण क्षेत्र में आज परियारी, मगरवाडा, दमणवाडा, और पटलारा में जनता के साथ जनसंवाद कर सभी नागरिकों को बडी संख्या में 5 जून को होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण दिया। पूर्व सांसद लालू पटेल ने जनता को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे प्रदेश को कई सौगाते दी है। 5 जून को फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी हमें एयरपोर्ट, भव्य सरकारी अस्पताल सहित अनेक सौगातें देने जा रहे हैं। हम सभी को बडी संख्या में उपस्थित रहकर मोदी जी का स्वागत एवं अभिवादन करना है। चारों पंचायतों के नागरिकों ने पूर्व सांसद लालू पटेल के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकारते हुए बडी संख्या में उपस्थित रहने का वादा किया। आज की इस जनसंवाद बैठकों में दमण जिला पंचायत प्रमुख धरम पटेल, परियारी सरपंच भाविक हलपति, दमण जिला पंचायत सदस्य मुकेश गोसावी, दमणवाडा सरपंच कल्पना हलपति, दमणवाडा उपसरपंच मिलन पटेल, मगरवाडा सरपंच भूपेंद्र पटेल, पटलारा सरपंच विजय पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं की उपस्थिति रही।

महाराष्ट्र और बंगाल में महिलाओं की योजना का लाखों अपात्र लोग ले रहे लाभ

राज्य सरकारें जांच के जरिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी योजनाएं अब पात्रता और पारदर्शिता के सवालों के घेरे में हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहिन योजना से करीब 80 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक बहस छिड़ गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाखों अपात्र लोगों के लाभ लेने का दावा किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए लाई गई इन योजनाओं का लाभ दोनों ही राज्यों में पुरुष भी ले रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाए गए हैं। दोनों राज्यों में सरकारें अब ई-केवाईसी, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की नई जांच के जरिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी हैं, जिससे इन महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें महाराष्ट्र में प्रदेश सरकार की लाड़की बहिन योजना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले करीब 80 लाख लाभार्थियों के खाते बंद कर दिए हैं। ये कार्रवाई योजना को लेकर आ रही शिकायत के बाद की गई है। इस योजना का फायदा अपात्र भी उठा रहे थे।

जांच में सामने आया था कि कुछ पुरुष और सरकारी कर्मचारी भी गलत तरीके से 1500 रुपए की मासिक राशि ले रहे थे। इस धांधली को रोकने के लिए वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी का अभियान शुरू किया गया था। वेरिफिकेशन में एक तकनीकी पेंच भी फंसा। रिपोर्ट के मुताबिक मराठी भाषा में पूछे गए एक सवाल के गलत जवाब की वजह से करीब 24 लाख महिलाओं को सरकारी कर्मचारी मान लिया गया था। हालांकि, बाद में हुई जांच में इनमें से 20 लाख महिलाएं पूरी तरह पात्र पाई गई थीं।

प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में लाभार्थियों की संख्या कम होने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा केवल ई-केवाईसी लंबित रहने से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं। तटकरे ने बताया कि सरकार ने ई-केवाईसी के लिए शुरुआती समयसीमा तय की थी, जिसे बाद में कई बार बढ़ाया गया। कुल मिलाकर लाभार्थियों को करीब 8 से 10 महीने का समय दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सत्यापन प्रक्रिया राज्य की सभी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में अपनाई जाती है, केवल लाड़की बहिन योजना तक सीमित नहीं है।

मंत्री तटकरे के मुताबिक पिछले 10 महीनों में किए गए डेटा सत्यापन में 11 से 12 लाख ऐसे लाभार्थी पाए गए, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 4.75 से 5 लाख महिलाएं 65 साल की आयु सीमा पार कर चुकी हैं, जिसके कारण वे योजना के दायरे से बाहर हो गईं। तटकरे ने बताया कि करीब 14 हजार सरकारी कर्मचारी भी लाभार्थियों की सूची में शामिल पाए गए थे, इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी चिन्हित किए गए हैं, जो अन्य योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। करीब 3.25 लाख लाभार्थियों के नाम पर पंजीकृत वाहन भी पाए गए हैं।

वहीं, बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर कहा था कि इस योजना का लाभ ले रहे करीब 30 लाख लाभार्थी अपात्र हैं। इनमें से कई गैर-भारतीय हैं या उनके नाम वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाए जा चुके हैं। सीएम अधिकारी ने नई 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना के लिए आवेदन फॉर्म जारी किया था। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन किया है या एसआईआर से जुड़े ट्रिब्यूनल में वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अपील की है, वे इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट चुके हैं और जिन्होंने ट्रिब्यूनल या सीएए के तहत आवेदन नहीं किया, वे भी योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार 1 जून से 90 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचायत क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। सीएम अधिकारी ने दावा किया कि सत्यापन की कमी के कारण योजना में पुरुष लाभार्थियों के नाम भी शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं 2 जून तक सफलतापूर्वक नामांकन करा लेंगी, उन्हें अगले कैबिनेट बैठक के बाद डीबीटी के जरिए राशि भेजी जाएगी।

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से ढहा मकान

-मलबे से सुरक्षित निकाले गए छह लोग

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भलस्वा डेरी के पास मुकुंदपुर इलाके से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के इशु विहार की गली नंबर 1 में सुबह अचानक एक एलपीजी सिलेंडर फट गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि लगभग 250 वर्ग गज में बना एक मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की पाँच गाड़ियाँ तुरंत मौके पर पहुँचीं। आपातकालीन और बचाव टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से फौरन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। राहत की बात यह रही कि अब तक मलबे के नीचे से दो महिलाओं सहित कुल छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस मकान में कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ रहते थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मलबे को हटाया जा रहा है।

बांद्रा में बिना अनुमति उड़ाए सैकड़ों ड्रोन, पुलिस ने मैनेजर को हिरासत में लिया

-ड्रोन समेत अन्य उपकरण जब्त, एक ड्रोन की कीमत करीब 80 हजार रुपए

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में बांद्रा पश्चिम में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निषेधाज्ञा और सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी करते हुए मैदान में करीब 200 से 250 ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही थी सूचना मिलने पर बांद्रा पुलिस की टीम ने मौके पर छापेमारी कर एक निजी कंपनी के मैनेजर को हिरासत में लिया और बड़ी संख्या में ड्रोन समेत अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक 28 मई की रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ को सूचना मिली थी कि बांद्रा पश्चिम स्थित विंग्स स्पोर्ट क्लब ग्राउंड में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर ड्रोन संचालन रुकवाया और मौके पर मौजूद व्यक्ति को हिरासत में लिया जिसकी पहचान गोपाल नारायण सिंह (45) के रूप में हुई, जो दक्षिण दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि वह बोल्डसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और कंपनी के विज्ञापन के लिए ड्रोन आधारित शूटिंग की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में गोपाल से ड्रोन संचालन की अनुमति, आवश्यक लाइसेंस और मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। हालांकि वह कोई वैध अनुमति पत्र या अधिकृत दस्तावेज पेश नहीं कर सका। जांच में कंपनी के एक अन्य पदाधिकारी सुनील गुप्ता का नाम भी सामने आया है, जो कई विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया देखता था। आरोप है कि मंजूरी प्राप्त किए बिना ही ड्रोन शो और शूटिंग शुरू कर दी गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हाई-टेक ड्रोन, कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेटिंग किट और एक लैपटॉप जब्त किया है।

आरे में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, 70,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन मुक्त

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई के गोरेगांव (पूर्व) स्थित आरे मिल्क कॉलोनी (यूनिट 32) में स्थित हजरत सैयद बरकत अली शाह बाबा दरगाह पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 70,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी दरगाह को ध्वस्त करने के लिए तीन बुलडोजर चलाए गए। यह कार्रवाई सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई और इसके मद्देनजर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आरोप है कि यह दरगाह दशकों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जबकि लोग इस दरगाह को पुरानी और वैध बताने का दावा कर रहे थे। आरे कॉलोनी एक सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, और ध्वस्तीकरण के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर संभावित सुरक्षा जोखिमों के बारे में जिला प्रशासन को पहले ही पत्र लिखकर अवगत कराया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की कड़ी निगरानी की जा रही थी। इस मुद्दे को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पिछले साल अप्रैल में प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने आरे कॉलोनी में कथित अवैध दरगाह और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। बीजेपी नेता सोमैया ने कार्रवाई से कुछ ही दिन पहले इस दरगाह का दौरा भी किया था।

सीएम योगी ने फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ किया

कुशीनगर (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान कर फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर की जनता को संबोधित कर ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी, जिसका लोगों द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सीएम योगी ने कहा कि अब यह क्षेत्र फाजिलनगर नहीं बल्कि पावागढ़ के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा और इस भगवान महावीर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों हम फाजिल कहे! और इस बदलाव को वर्तमान पीढ़ी का बड़ा सौभाग्य बताया। मुख्यमंत्री योगी ने संकेत दिया कि लोगों की मांग पर विधायक और सांसद मिलकर काम कर रहे थे, और अब नामकरण का प्रस्ताव भी आगे बढ़ा दिया गया है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का जिक्र कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 498 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता ने राम मंदिर को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया था, और कई पीढ़ियों तक मंदिर निर्माण में बाधाएं आती रहीं। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन की भाजपा सरकार के प्रयासों से ही राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हो सका, जबकि कांग्रेस और सपा जैसे दल इसके मार्ग में रोड़े अटका रहे थे और घोषित रामद्रोही थे। मुख्यमंत्री योगी ने मतदाताओं की शक्ति पर जोर देकर कहा कि फाजिलनगर, पडरौना, खड्डा या हाटा जैसे क्षेत्रों में दिया गया एक-एक वोट लखनऊ और दिल्ली में अपनी ताकत दिखाता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि इसी वोट की शक्ति से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, और पाकिस्तान को थर्रा देने वाली मिसाइलों का निर्माण लखनऊ में हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति

-न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हुई

-एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा समेत पांच नामों को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली,(ईएमएस)। देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि अब केवल एक पद रिक्त रह गया है। नियुक्त किए गए नए न्यायाधीशों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मोहना शामिल हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन सभी की नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रभावी हो गई है। यह नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के बाद हुई हैं। इस अध्यादेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। बढ़ते मुकदमों और लंबित मामलों के दबाव को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। कानून मंत्रालय के अनुसार, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए संविधान पीठों का गठन अधिक नियमित रूप से किया जा सकेगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी समयबद्ध न्याय मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की

वंदे मातरम के पांच अंतरे हर कार्यक्रम में अनिवार्य करना अनावश्यक और बोझिल

-शशि थरूर ने वंदे मातरम के सभी पांच अंतरे गाए जाने की अनिवार्यता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने आधिकारिक कार्यक्रमों के शुरुआत और अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी पांच अंतरे गाए जाने की अनिवार्यता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। केरल में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर छिड़े एक नए विवाद के बीच, थरूर ने इस प्रथा को श्रोताओं के लिए अनावश्यक और बोझिल बताया है। केरल में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर जारी विवाद के बीच थरूर ने कहा कि वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हर समारोह में इसके सभी अंतरे बजाने को अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं। इसका पहला अंतरा या शुरुआती दो अंतरे, ज्यादातर लोगों को मुंह जुबानी याद होते हैं। थरूर ने कहा कि परंपरागत रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगान अलग से, अक्सर अंत में बजाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में पांचों अंतरे गाए जाएं। मुझे लगता है कि यह एक अनावश्यक थोपा हुआ नियम है। थारूर ने जोर दिया कि उन्हें राष्ट्रगीत से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। मैं खुशी-खुशी इसे आपके लिए गा सकता हूं।

बता दें वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया। यह मूल रूप से संस्कृत और बंगाली भाषा के मिश्रण में लिखा गया है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा। साल 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे राजनीतिक मंच पर गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा।

टीएमसी के 50 विधायक बदल सकते हैं पाला

-चुनाव चिन्ह भी पड़ सकता है खतरे में

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्ता से बेदखल हुई टीएमसी अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के 50 विधायक पाला बदलने के लिए सौदेबाजी करते सुनाई दे रहे हैं। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा सोमवार को दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि टीएमसी के करीब 50 विधायक पार्टी से अलग हो सकते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कई पार्षद लगातार अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी के बड़े नेता आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। दो विधायकों के निष्कासन के बाद अब विधानसभा में टीएमसी के सदस्यों की संख्या घटकर 78 रह गई है। राजनीतिक हल्कों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि निष्कासित विधायक रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में एक नई तृणमूल का गठन किया जा सकता है, हालांकि अभी तक किसी भी नेता ने इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।

दूसरी तरफ, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इन दोनों विधायकों का विशेष रूप से जिक्र किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, हावड़ा की उलुबेरिया पूर्व सीट से विधायक रीताब्रत बनर्जी और मध्य कोलकाता के एंटाली से विधायक संदीपन साहा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर ही विधानसभा सचिवालय ने विधायक दल के जाली हस्ताक्षर का मामला पुलिस में दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह जांच किसी अन्य दल द्वारा शुरू नहीं की गई थी, बल्कि खुद टीएमसी के इन दो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। विधायकों का आरोप था कि विपक्ष के नेता के चयन से संबंधित बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ था और 70 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत है। इस पूरे विवाद ने बंगाल की सियासत को बेहद संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है।

तो महाराष्ट्र जैसी बन जाएगी स्थिति

यदि टीएमसी के 50 विधायक अलग होकर एक नया गुट बनाते हैं, तो बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल सकता है। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में बड़ी बगावत के बाद मूल कमानों को अपनी ही पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न गंवाना पड़ा था, वैसी ही स्थिति यहाँ भी बन सकती है। टीएमसी नेतृत्व ने जिन दो विधायकों पर कार्रवाई की है, उन्हें भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बावजूद वे आधिकारिक बैठकों से लगातार नदारद रहे और खुद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किया। पार्टी उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि इन विधायकों के बयान और कदम संगठन के हितों के पूरी तरह खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया।

भजनलाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात, सरकार के कामकाज का दिया फीडबैक

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की। प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र यह मुलाक़ात अहम मानी जा रही है। सीएम भजनलाल ने सरकार के कामकाज को लेकर भी पीएम मोदी को फीडबैक दिया। जानकारी के मुताबिक सोमवार को करीब एक घंटे से ज्यादा दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। वहीं इस मुलाक़ात को प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों से भी जोड़ जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन असल वजह क्या है? ये कोई पुख्ता नहीं कर रहा। बता दें पिछले तीन महीने में सीएम की पीएम मोदी से यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले फ़रवरी और मार्च महीने में भी पीएम से मुलाक़ात हुई थी। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं सहित आगामी योजना की जानकारी पीएम मोदी को दी, साथ ही केंद्र के साथ मिलकर चल रही योजनाओं पर भी चर्चा की।

अन्नामलाई ने नितिन नवीन से की मुलाकात, अटकलों का दौर जारी

-राज्यसभा और संगठन में नई भूमिका को लेकर चर्चाएं गर्म

नई दिल्ली(एजेंसी)। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच उनकी दिल्ली यात्रा ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाने की अफवाहों के बीच अन्नामलाई ने पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संन्तोष से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक में उनके संभावित नए दायित्वों और संगठन में भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चा हुई।

जानकारी के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने अन्नामलाई को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनकी क्षमता और संगठनात्मक योगदान के अनुरूप उन्हें आगे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती रहेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली प्रवास के दौरान वह पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। अन्नामलाई की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब उनके भाजपा छोड़ने, नई राजनीतिक पार्टी बनाने अथवा राज्यसभा भेजे जाने जैसी संभावनाओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि उन्होंने इन अटकलों पर खुलकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। दिल्ली आने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केवल इतना कहा था, 'कृपया इंतजार कीजिए, दो दिन बाद हम बैठकर बात करेंगे।' उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और बढ़ा दी है।

बहुत कम समय में पार्टी का प्रमुख चेहरा बने

पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई वर्ष 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। कम समय में ही उन्होंने तमिलनाडु में पार्टी के प्रमुख चेहरों में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2021 से 2025 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कई राज्यव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया और युवाओं तथा सोशल मीडिया पर मजबूत जनाधार तैयार किया। हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हुईं, क्योंकि पार्टी का प्रमुख चेहरा होने के बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए त्रिभाषा नीति को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी ने भी राजनीतिक बहस को हवा दी और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल भाजपा नेतृत्व और अन्नामलाई की बैठकों पर सभी की नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में उनकी भूमिका को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है।

नीट मामला और प्रशासनिक चूकों को लेकर युवा कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से तत्काल हटाए जाने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और प्रशासनिक चूकों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने देशव्यापी आंदोलन को और उग्र करने का ऐलान किया है। युवा कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तत्काल हटाए जाने की अपनी मांग को दोहराया है। कांग्रेस की युवा इकाई ने साफ कहा है कि परीक्षाओं से जुड़े बार-बार के विवादों ने देश की शिक्षा व्यवस्था और चयन प्रक्रियाओं में छात्रों के भरोसे को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है।

कांग्रेस की युवा इकाई ने कहा कि वह कई राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का नया चरण शुरू करेगी जिसके तहत मशाल जुलूस निकाले जाएंगे, छात्रों से संपर्क करने के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और प्रदर्शन एवं घेराव किया जाएगा। संगठन ने कहा कि परीक्षाओं संबंधी बार-बार पैदा होने वाले विवादों से शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए कई राज्यों का दौरा करेंगे। यह अभियान महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चलाया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा संबंधी अनियमितताएं होने और प्रशासनिक चूक के कारण छात्रों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने परीक्षाएं कराने से जुड़ी संदिग्ध संस्थाओं को ठेके दिए जाने संबंधी खबरों पर भी चिंता जताई। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा कि इस देश के छात्र रोजगार, न्याय और जवाबदेही के हकदार हैं। इसके बजाय उन्हें प्रश्नपत्र लीक, अनिश्चितता और चरमराई हुई परीक्षा व्यवस्था मिली है। उन्होंने कहा कि संगठन अपना विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखेगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं होती और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को हटाया नहीं जाता।

चिब ने सरकार पर छात्रों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि परीक्षाओं के पेपर लीक होने एवं अनियमितताओं के कारण युवा अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब हम इस आंदोलन को पूरे देश में तेज कर रहे हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के लिए मजबूर नहीं हो जाते।

सिंधु जलसंधि पर खेल-1 अगस्त से भारत कर रहा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट्स का काम शुरू

-चिनाब नदी के पानी को ब्यास नदी बेसिन में मोड़ा जाएगा, 2029 तक का लक्ष्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार इस साल 1 अगस्त से अपने सबसे महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो प्रोजेक्ट्स में से एक पर काम शुरू करने जा रही है। करीब 2,300 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 31 जुलाई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तहत चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी बेसिन में मोड़ा जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनएचपीसी के एक दस्तावेज के मुताबिक 'लिंक-3 प्रोजेक्ट' हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की लाहौल घाटी में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। इस योजना के तहत चिनाब नदी पर 19 मीटर ऊंचा बैराज बनाया जाएगा। इसके साथ एक इंटेक स्ट्रक्चर और करीब 8.7 किलोमीटर लंबी जल परिवहन सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में जलविद्युत उत्पादन की भी संभावना रखी गई है। दस्तावेज में बताया गया है कि प्रस्तावित बैराज के आसपास का इलाका बेहद दुर्गम और पहाड़ी है। यहां चिनाब नदी एक चौड़ी यू-आकार की घाटी से होकर बहती है। क्षेत्र की ऊंचाई करीब 3,095 मीटर से लेकर 6,517 मीटर तक है और यहां तीखी पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी घाटियां मौजूद हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक करीब 8.7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग चिनाब बेसिन के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली में पहुंचाएगी। इस परियोजना को पाकिस्तान के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चिनाब सिंधु जल संधि के तहत पश्चिमी नदियों में शामिल है, जिन पर भारत के अधिकार सीमित रहे हैं। हालांकि, पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को लेकर कड़ा रुख अपना लिया था। पानी मोड़ने का प्रस्तावित स्थल कोस्कर गांव के पास स्थित है और यह अटल टनल रोहतांग के उत्तरी छोर से आगे पड़ता है।

इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग या जलविद्युत परियोजना नहीं है, बल्कि पश्चिमी नदियों के पानी के बेहतर उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय नीति निर्माताओं और जल विशेषज्ञों का लंबे समय से मानना है कि पश्चिमी नदियों का काफी पानी पर्याप्त भंडारण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की ओर बह जाता है। चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना को इसी समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से उत्तर भारत में जलविद्युत उत्पादन की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। अधिकारियों के मुताबिक दूसरे चरण में पानी के इस नए प्रवाह का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हिमालयी नदियों को भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों में गिना जाता है। ऐसे समय में जब देश थर्मल पावर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, यह परियोजना ऊर्जा और जल प्रबंधन दोनों दृष्टि से अहम मानी जा रही है।

कडैया ग्राम पंचायत की टीम ने नये एयरपोर्ट का किया दौरा:प्रशासक प्रफुल पटेल के विजन की तारीफ की

– कडैया ग्राम पंचायत सरपंच शंकर पटेल ने कहा: दमण में एयरपोर्ट की सुविधा से पर्यटन उद्योग को मिलेगी ऊंची उडान

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 2 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दमण दौरे से पहले दमण के विभिन्न प्रोजेक्टों का सरपंचो, जिला पंचायत सदस्यों, भाजपा के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दौरा किया जा रहा है। आज इसी क्रम में कडैया ग्राम पंचायत सरपंच शंकर पटेल और उनकी टीम ने दमण के नये एयरपोर्ट टर्मिनल की मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टर्मिनल की सुविधाओं एवं एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण सहित के कार्यों को नजदीक से देखा। कडैया ग्राम पंचायत की टीम ने अद्भूत और आधुनिक एयरपोर्ट की सुविधा तैयार करने वाले प्रशासक प्रफुल पटेल के विजन को सलाम करते हुए खुलकर तारीफ की। सरपंच शंकर पटेल ने कहा कि दमण में एयरपोर्ट शुरू हो जाने से दमण के पर्यटन उद्योग को नई उडान मिलने वाली है। इससे यहाँ के नागरिकों को काफी लाभ मिलने वाला है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/कलेक्टर, दमण के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शन के तहत

निर्वाचन कार्यालय, SIR, SVEEP टीम द्वारा भीमपोर पंचायत, वार्ड नंबर 4 और मरवड़ पंचायत के साथ जागरूकता कार्यक्रम किया गया

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 2 जून। दिनांक 01.06.2026 और 02.06.2026 दमन प्रशासन, एस एस.आई.आर. (SIR) SVEEP, निर्वाचन विभाग टीम द्वारा SVEEP गतिविधि का आयोजन भीमपोर ग्राम पंचायत में श्री उदय पटेल, सरपंच एवं पंचायत सदस्यों के समन्वय से किया गया। वार्ड क्रमांक-4 में यह गतिविधि वार्ड पार्षद श्रीमती प्रवीना राणा के सहयोग से आयोजित की गई। यह कार्यक्रम नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती दीपिका टंडेल के समन्वय में आयोजित किया गया, जिसमें अन्य पार्षदगण श्रीमती सिंपल कटेला, श्रीमती नीला प्रमोद राणा, श्रीमती कपिला ओड तथा श्रीमती भाविका टंडेल ने भी सहभागिता एवं सहयोग प्रदान किया। मारवाड़ ग्राम पंचायत में यह गतिविधि श्री सोमा भाई एवं पंचायत सदस्यों के समन्वय से आयोजित की गई। इस दौरान SVEEP टीम द्वारा समाज के सदस्यों को SIR प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि 4 जून से 3 जुलाई तक BLO द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन एवं संबंधित कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सुचारू, पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से तैयार करना तथा नागरिकों को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन विभाग की एस. आई.आर. स्वीप टीम द्वारा नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सभी मतदाताओं से खास अनुराध किया गया कि जब बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 04.06.2026 से 03.07.2026 तक उनके घर आएं, तो वे अपना पूरा सहयोग दें ताकि रिवीजन प्रक्रिया आसानी से हो सके एवं यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचाने की अपील की गई। टीम द्वारा अनुरोध किया गया है कि टीम द्वारा सुनिश्चित करें कि उनका नाम वर्ष 2002 की पूर्व एस.आई.आर. मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। यदि जानकारी उपलब्ध न हो, तो संबंधित मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं, निर्वाचन विभाग कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा संबंधित वेबसाइट पर आवश्यक विवरण भरकर अपना नाम खोज सकते हैं। या https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर "search your name in last SIR" का इस्तेमाल करके ज़रूरी डिटेल्स डालकर या चीफ इलेक्शन ऑफिसर, DNH और DD की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ceoddd.in पर "search by details" या "search by EPIC Number" या "search by Polling Station" पोर्टल में मौजूद ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं। यदि पिछले SIR-2002 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं मिलता है, तो मतदाताओं को अपने माता-पिता के नाम की पुष्टि करनी होगी। यदि माता-पिता के नाम की भी पुष्टि नहीं हो पाती है, तो संबंधित मतदाता को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे और उन्हें अपने क्षेत्र के BLO अथवा निर्वाचन विभाग, दमन में जमा करनेहोंगे। आवश्यक दस्तावेजों में केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी हेतु जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पूर्व जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। चुनाव विभाग ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक पात्र मतदाता को प्रक्रिया में शामिल करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं की सहायता हेतु प्रत्येक रविवार को ''बूथ डे'' घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित बूथों पर प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अधिकारियों एवं बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO२) की उपस्थिति रहेगी, जहां मतदाता अपने नाम की जांच, संशोधन एवं अन्य निर्वाचन संबंधी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। मतदाताओं की सहायता हेतु दमन निर्वाचन विभाग द्वारा कलेक्टर कार्यालय, मोटी दमन में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 एवं 18002330530 के माध्यम से भी निर्वाचन विभाग से संपर्क किया जा सकता है। यह पुनरीक्षण प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः दमन के सभी नागरिकों से सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा की गई है।

श्री जगन्नाथ धाम पूरी उत्सव सम्पन्न

दमण, 1 जून। त्रिवेणी कल्चरल सेंटर कटक ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता एवं उत्सव 24 मई 2026 को पूरी में आयोजित किया था। इस स्पर्धा में भारत देश से कई स्पर्धको ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रज्ञा संस्कृति अकादमी के बच्चों ने हिस्सा लिया था एवं जीत हासिल कर दादरा नगर हवेली एवं दमण-दीव का नाम रोशन किया। इस स्पर्धा के अंतर्गत नृत्य तथा ड्राइंग कम्पटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रज्ञा संस्कृति अकादमी से छात्रा दिया निगम, वृंदा भानुशाली, अनाया पटेल, चित्रा निगम, नैनिका नेगी और लिझा पाटिल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके ग्रुप सेमी क्लासिकल भरतनाट्यम जूनियर केटेगरी में प्रथम स्थान और हिमानी सिद्धा, द्विती पटेल और कांक्षति कामली ने ग्रुप क्लासिकल भरतनाट्यम सीनियर नृत्य केटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इसके उपरांत सोलो नृत्य केटेगरी में इंटरनेशनल लेवल पर तश्वी भट्ट ने प्रथम पुरस्कार और नेशनल लेवल पर द्वितीय स्थान जीता, नेशनल लेवल क्लासिकल भरतनाट्यम में अनाया पटेल ने जूनियर केटेगरी में प्रथम पुरस्कार और द्विति पटेल ने सीनियर केटेगरी में प्रथम पुरस्कार जीता तथा सेमी क्लासिकल श्रेणी में देवांगी देसाई ने ओपन केटेगरी में प्रथम पुरस्कार, हिमानी सिद्धा ने सीनियर केटेगरी में प्रथम पुरस्कार एवं कांक्षति कामली ने द्वितीय पुरस्कार, दिया निगम ने जूनियर केटेगरी में प्रथम पुरस्कार और चित्रा निगम ने द्वितीय पुरस्कार जीता एवं डुएट सेमी क्लासिकल केटेगरी में वृंदा भानुशाली और दिया निगम ने प्रथम पुरस्कार जीता।

प्रज्ञा संस्कृति अकादमी से तनिषा सिद्धा ने ड्राइंग कम्पटीशन में प्रथम तथा आरुष दलाई ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कलागुरु जहान्वी देसाई ने भी फेस्टिवल केटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके बेस्ट परफार्मेंस का अवॉर्ड एवं कला उपासक का अवॉर्ड भी जीता तथा संघप्रदेश दानह तथा दमण-दीव का नाम रोशन किया।

प्रज्ञा संस्कृति अकादमी दमण ने जीता अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता

संघ प्रदेश प्रशासन दानह और दमण एवं दीव,
सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय,
जिला पंचायत, दमण

निविदा आमंत्रण सूचना

दमण जिला में स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कपीगाम (संघ प्रदेश प्रशासन दानह और दमण और दीव) में "शाला प्रवेशोत्सव" के लिए विविध सेवाएँ और सहायक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु "समग्र सेवाएँ प्रदान करने वाली एजेंसी" के चयन के लिए प्रस्ताव का अनुरोध।

ई-निविदा संख्या: 06/2026-27
टेंडर ID: 2026_DAMAN_4814_1
F. No ADE/DP/DMN/Shala_Praveshotsav/2026/284

अधिक जानकारी के लिए, कृपया QR कोड स्कैन करें	डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 05/06/2026
	हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 05/06/2026
https://ddtenders.gov.in	बोली खुलने की तिथि 05/06/2026

सहायक शिक्षा निदेशक कार्यालय, जिला पंचायत, दमण
IP/DMN/2/5/2026-27-210 DTD:-02/06/2026

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमण एवं दीव प्रशासन,

शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, जिला पंचायत, दीव.
निविदा सूचना सं. EDN/DP/DIU/PM Poshan/Cent.Kitchen/2026-27/62, Dated: - 29/05/2026

ई-निविदा आईडी :2026_DIUDT_4807_1
"दीव जिले में केंद्रीकृत रसोई प्रणाली (Centralized Kitchen System) के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों को दैनिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (RFP)"

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:	23/06/2026 से 16:00 समय
तकनीकी बोली खुलने की तिथि :	24/06/2026 से 09:00 समय
वित्तीय बोली खोलने की तिथि :	भौतिक नमूना और तकनीकी बोली
अन्य विवरण :	में अर्हता प्राप्त करने के बाद

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें ddtenders.nic.in www.diu.gov.in ई-मेल: eodp.diu-dd@gov.in 02875-252733

शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, जिला पंचायत, दीव.
IP/DMN/2/5/2026-27-209 DTD:-02/06/2026

CHANGE OF NAME

I SUSHIL MAVJI CHAUHAN **S/O MAUGI GESSA** R/O HOUSE NO. 1881-9, GANDHIPARA, DIU, DAMAN AND DIU-362520, **I HAVE CHANGED MY NAME TO SUSHIL MAUGI.**

गुजरात की 34 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को मिली आधुनिक स्पोर्ट्स किट्स

गांधीनगर (ईएमएस)। राज्य की सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा बचपन से ही खेलों के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न सिंह वाजा एवं शिक्षा राज्य मंत्री रिवाबा जाडेजा के मार्गदर्शन में 'समग्र शिक्षा, गुजरात' के तहत राज्य की 34,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। 'समग्र शिक्षा' द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप खेलों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। स्कूलों को उपलब्ध कराई गई इन आधुनिक स्पोर्ट्स किट्स में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न खेल सामग्रियां शामिल की गई हैं।

CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY NAME FROM JESHALBEN PRADEEPKUMAR PUNAMIYA TO **JESHAL UPSHAM SHAH** AS PER DOCUMENT.
ADDRESS :1051-1, BUNGLOW NO.2,B/H WOODLAND IN,TOKARKHADA,SILVASSA - 396230

CHANGE OF NAME

I HAVE CHANGED MY NAME FROM SUMITRABEN MAHENDRAKUMAR SOLANKI TO **SUMITRABEN MAHENDRASINH SOLANKI** AS PER DOCUMENT.
ADDRESS : SUSHI MANGAL,50 VRUNDAVAN SOCIETY,B/H ADIVASI BHAVAN,SILVASSA - 396230

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान-ईयू के संयुक्त बयान को भारत ने किया खारिज, कहा- यह हमारा आंतरिक मामला

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत ने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करने वाले पाकिस्तान और यूरोपीय संघ (ईयू) के संयुक्त बयान को सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं तथा किसी भी बाहरी पक्ष को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों पर संयुक्त बयान में किए गए ऐसे "अनावश्यक और बेवजह" उल्लेख को पूरी तरह अस्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि जिन पक्षों का इन मामलों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उन्हें इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पाकिस्तान-ईयू संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया गया था। बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा, जबकि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन संघर्ष पर जानकारी साझा की। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने की बात कही थी। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े मुद्दे पूरी तरह भारत के आंतरिक विषय हैं। नई दिल्ली का कहना है कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मामलों में किसी तीसरे पक्ष की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। यह रुख भारत पहले भी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों और अन्य देशों के बयानों के संदर्भ में स्पष्ट करता रहा है। भारत की इस प्रतिक्रिया को उसकी लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक नीति के अनुरूप माना जा रहा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दों को द्विपक्षीय या आंतरिक विषय बताया जाता रहा है।

बालेन्द्र शाह ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन को निमंत्रित कर अपनी जगहँसाई करवा ली है

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है।

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहा पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की चौंकाने वाली और कई मायनों में अपरिपक्व बयानबाजी बनी है। संसद में उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। हालात इतने असहज हो गए कि कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। और विडंबना देखिए, भारत को घेरने की कोशिश में दिया गया बयान नेपाल में ही प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ गया। विपक्ष, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राजदूत और सीमा विशेषज्ञ तक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सबूत, स्पष्टीकरण, यहां तक कि माफी की मांग होने लगी। सीमा विवाद पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाने के बजाय बालेन्द्र शाह की टिप्पणियां ऐसी साबित हुईं जिन्होंने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने दोनों देशों से तथ्यों का अध्ययन कर मित्रवत तरीके से विवाद सुलझाने की अपील की। उधर, नेपाल में विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने बालेन्द्र शाह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और अन्य नेताओं ने संसद के अभिलेखों से बयान हटाने की मांग की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य और दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री की बातों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया। इस प्रकार बालेन्द्र शाह का बयान भारत से अधिक नेपाल के भीतर ही विवाद का विषय बन गया।

दरअसल, सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र हैं। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख दर्रे के नीचे स्थित स्रोतों से होता है और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कालापानी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। यही मूल

विवाद दोनों देशों के दावों की जड़ में है।

हम आपको बता दें कि विवाद को हाल में उस समय नया मोड़ मिला जब नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लगातार संचालित हो रही है और यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि एकतरफा तरीके से क्षेत्रीय दावों का विस्तार न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही स्वीकार्य है।

उधर, बालेन्द्र शाह के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। मंत्रालय के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों की कमी, दशगजा क्षेत्र और सीमापार भूमि उपयोग जैसी व्यावहारिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दोनों ओर के लोग एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत, तकनीकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लेकिन सबसे अधिक हैरानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उस सुझाव पर हुई जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी की बात उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान सीमाओं की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव न केवल व्यावहारिक दृष्टि से कमजोर माना गया बल्कि नेपाल के भीतर भी इसे अपरिपक्व और अनावश्यक बताया गया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हमेशा द्विपक्षीय ढांचे में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में तीसरे पक्ष को बीच में लाने की बात कूटनीतिक परंपराओं और स्थापित समझ से मेल नहीं खाती।

इसके अलावा, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील और पूर्णतः द्विपक्षीय विषय में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव बालेन्द्र शाह की कूटनीतिक नासमझी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसने कई जानकारों को हैरान कर दिया। भारत दशकों से स्पष्ट करता आया है कि वह अपने किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल को स्वीकार नहीं करता, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चीन का हो या नेपाल का। ऐसे में ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर बुलाने का प्रस्ताव शुरू से ही अव्यावहारिक और वास्तविकताओं से कटा हुआ नजर आया। जिस देश ने दो शताब्दियों पहले उपमहाद्वीप छोड़ दिया, उसे आज की सीमा वार्ताओं में घसीटने की कोशिश को कई पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक अपरिपक्वता बताया। दिलचस्प यह है कि बालेन्द्र शाह की इस टिप्पणी पर केवल नेपाल में ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के रणनीतिक और दक्षिण एशियाई मामलों पर नजर रखने वाले हलकों में भी हैरानी जताई गई और इसे अव्यावहारिक सोच का उदाहरण माना गया। कूटनीति की दुनिया में जहां गंभीरता, तैयारी और यथार्थवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, वहां बालेन्द्र शाह का यह सुझाव कई लोगों को ऐसा लगा मानो किसी जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए इतिहास की धूल झाड़कर ऐसे पात्रों को मंच पर बुलाने की कोशिश की जा रही हो जिनकी अब उस प्रक्रिया में कोई वास्तविक भूमिका ही नहीं बची है।

देखा जाये तो सामरिक दृष्टि से लिपुलेख क्षेत्र का महत्व अत्यंत गहरा है। यह भारत, नेपाल और चीन के त्रिसीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। यह केवल धार्मिक यात्रा का मार्ग नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र में संपर्क, निगरानी और रणनीतिक पहुंच का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चीन की बढ़ती सक्रियता और हिमालयी क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच यह इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और भी संवेदनशील हो गया है। इसलिए इस क्षेत्र से जुड़ा कोई भी राजनीतिक बयान केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके व्यापक सामरिक प्रभाव भी होते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान इसी कारण अधिक विवादास्पद बन गया। बिना पर्याप्त तैयारी और तथ्यों की मजबूत प्रस्तुति के ऐसे संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करना न केवल कूटनीतिक भ्रम पैदा करता है बल्कि अपने ही देश की आधिकारिक स्थिति को कमजोर भी कर सकता है। यही कारण है कि उनकी टिप्पणियों के तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा और देश के अनेक राजनीतिक तथा कूटनीतिक विशेषज्ञों ने उनकी आलोचना की।

बहरहाल, यह पूरा प्रकरण एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े मतभेद अवश्य हैं, लेकिन दोनों देशों ने बार-बार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान की प्रतिबद्धता जताई है। ऐसे समय में भावनात्मक या बचकाने राजनीतिक बयान समाधान का रास्ता नहीं खोलते, बल्कि अनावश्यक भ्रम और विवाद को जन्म देते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की हालिया टिप्पणियां इसी का उदाहरण बन गई हैं, जहां भारत पर निशाना साधने की कोशिश से अधिक नुकसान उन्हें अपने ही देश के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में उठाना पड़ा है।

संपादकीय

विराट और वैभव

भले ही फटाफट क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला आईपीएल बाजार और नई पीढ़ी के जुनून का संगम हो, लेकिन लोकप्रियता के नये आयाम तय करता यह खेल अब दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे चमकीले सितारे बनकर उभरे टी-20 सनसनी वैभव सूर्यवंशी। महज पंद्रह साल की उम्र में उनकी कामयाबी हैरत में डालने वाली है। वहीं अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने खास अंदाज में सबका ध्यान आकर्षित किया। इस 37 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर ने फाइनल में तूफानी अर्धशतक लगाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लगातार दूसरी बार ट्रॉफी दिलाई। दो महीने तक चले इस टूर्नामेंट में कोहली की फॉर्म और फिटनेस शानदार रही है। यही वजह है कि वर्ष 2027 एकदिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में उनकी भागीदारी अब लगभग तय लग रही है। खुद कोहली ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी मनःस्थिति में बदलाव लाने और युवा खिलाड़ियों से थोड़ा सीखने की जरूरत थी, ताकि वे टी-20 क्रिकेट में अपने खेल को नये सिरे से निखार सकें। यह सुखद ही है कि इस दिग्गज क्रिकेटर की यह ईमानदार स्वीकारोक्ति भारतीय क्रिकेट को आकार दे रही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की खूबसूरत बानगी को ही दशार्ती है। निस्संदेह, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन ने साफ दिखाया कि दो पीढ़ियों के क्रिकेटर कैसे एक-दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। वास्तव में, विराट कोहली आज भी एक प्रभावशाली खिलाड़ी की छवि को बनाये हुए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी जैसे उदीयमान खिलाड़ी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस फटाफट क्रिकेट में खेल का निरंतर विकास होता रहेगा। यह सुखद ही है कि राजस्थान रॉयल्स के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी सूर्यवंशी ने अधिकांश पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मसलन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप विजेता और सुपर सिक्स ऑफ द सीजन जैसे खिताब हासिल किए।

चिंतन-मनन

सच्चा मित्र संजीवनी की तरह

हम सभी के परिचित और दोस्त होते हैं। भले ही बचपन के, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या आस-पास कॉलोनी में रहने वाले हों, मित्र तो सभी के होते हैं। सच्चा मित्र बनना और बनाना हर इंसान की इच्छा होती है। लेकिन, सच्चे मित्र बहुत कम मिल पाते हैं। ऐसा मित्र, जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसके साथ अपनी हर बाते शेयर कर सकें। धर्मशास्त्रों में सच्चा मित्र उसे कहा गया है, जो सुख-दुख में साथ दे। ऐसे दोस्त से कभी भी डर नहीं लगता। ये सही रास्ते पर चलने में हमारे मददगार होते हैं। लेकिन, ऐसा दोस्त कौन है? क्या वह जो सिर्फ परिचित है? सच्ची दोस्ती प्रेम, विश्वास व भरोसा, एक-दूसरे का ख्याल रखने और चिंताओं पर ही आधारित होती है। क्या, कभी इस प्रश्न का उत्तर आपने खुद से पूछा है?

प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। हमारे परिचित अनेक हों, किंतु परामर्शदाता ईश्वर एक ही है। ईश्वर ही सच्चा दोस्त है, जो जीवन के हर पल में हमारी परछाई बनकर साथ रहता है। उस पर अपनी आंखें बंद कर, विश्वास व भरोसा करते हैं। जब सुखी या दुखी होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के रूप में उससे बातें करते हैं। जीवन की हर बात उससे साझा करते हैं और फिर खुद को हल्का महसूस करते हैं। किसी भी कार्य की शुरूआत हम ईश्वर से आशीर्वाद लेकर ही करते हुए कहते हैं-हे मेरे मालिक, मुझ पर अपनी छत्र-छाया बनाए रख, मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे सफलता प्रदान कर।

कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति में साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष भी हमें ही देता है। कोई मित्र हमारे यहां खाता-पीता है, किंतु विपत्ति के वक्ति दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह हमारा अंतरंग बन कर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही शत्रु बनकर मुंह फेर लेता है। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, लेकिन उस पर तुरंत विश्वास मत करो। अपमान, अहंकार और विश्वासघात के कारण मित्रता टूट जाती है। कभी ऐसा भी होता है, जिस दोस्त पर हम सबसे ज्यादा विश्वास व भरोसा करते हैं, वही विश्वासघात करता है और हृदय पर चोट लगने पर मित्रता टूट जाती है।

अगर, हम संकट और दरिद्रता में मित्र का साथ दें तो उसकी समृद्धि और विरासत के साझेदार बन सकते हैं। सच्चा दोस्त जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उससे घर-परिवार व समाज में पहचान बनती है। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है। जिसे मिल जाता है, समझो उसे खजाना मिल गया। ऐसे मित्र की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। सच्चा मित्र असल में संजीवनी है। इंसान जैसा है, उसका मित्र भी वैसा ही होगा।

विश्व साइकिल दिवसः प्रदूषण पर भाषण बहुत हुए, अब घर के कोने से साइकिल निकालिए

दिलीप कुमार पाठक

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर व्यक्ति समय की कमी और तनाव की शिकायत करता है, तब एक बेहद साधारण और किफायती समाधान हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। वह समाधान है - साइकिल। आज 3 जून को पूरी दुनिया विश्व साइकिल दिवस मना रही है। यह दिन किसी आधुनिक आविष्कार का जश्न नहीं, बल्कि उस सादगी और उपयोगिता को याद करने का अवसर है, जिसे हमने विकास की अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जब पूरी दुनिया महंगे ईंधन, ट्रैफिक जाम और जहरीले धुएं से हांफ रही है, तब साइकिल एक सुगम साधन की तरह नजर आती है। यह कोई साधारण सवारी नहीं, बल्कि बिना धुएं वाली वह मूक क्रांति है जो व्यक्ति की सेहत, जेब और धरती तीनों को एक साथ संवार सकती है।

आजकल की जीवनशैली को देखें तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। घर से महज दो कदम दूर सब्जी की दुकान या दूध की डेयरी तक जाने के लिए भी लोग तुरंत मोटरसाइकिल या कार की चाबी उठा लेते हैं। नतीजा यह हुआ है कि शहरों की हवा भारी हो चुकी है, सड़कों पर पैदल चलने की जगह नहीं बची और इंसानी शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। लोग शारीरिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए हर महीने जिम में हजारों रुपये खर्च करते हैं और एक ही जगह खड़े होकर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। जबकि इसका सबसे आसान और प्राकृतिक विकल्प हमारी दिनचर्या में ही छुपा है। सुबह या शाम को सिर्फ आधा घंटा साइकिल चलाना दिल को मजबूत करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है।साइकिल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। इसके लिए न तो महंगे पेट्रोल-डीजल की जरूरत होती है और न ही किसी भारी-भरकम मेंटेनेंस या सर्विसिंग के खर्च की। यह आत्मनिर्भरता और बचत का सबसे पहला और सच्चा पाठ पढ़ाती है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई हैं, तब साइकिल जमीन पर उतरकर इसका व्यावहारिक समाधान देती है। अगर किसी भी शहर का हर तीसरा व्यक्ति अपने छोटे-मोटे स्थानीय कामों के लिए गाड़ियों को छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।कई विकसित देशों ने इस बात को गहराई से समझा है और साइकिल को अपनी मुख्य जीवनशैली का हिस्सा बनाया है। वहाँ बड़े-बड़े अधिकारी और सजग नागरिक गर्व से साइकिल से दफ्तर जाते हैं। हमारे देश में भी अब धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है और शहरों में साइकिलिंग ग्रुप्स का चलन देखने को मिल रहा है। हालांकि, इस बदलाव को एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता और बुनियादी ढांचे दोनों में सुधार करना होगा। आज भी हमारे शहरों की सड़कें सिर्फ बड़ी और तेज रफ्तार गाड़ियों के हिसाब से बनाई जाती हैं। साइकिल चालकों के लिए अलग सुरक्षित लेन न होने के कारण लोग सड़कों पर निकलने से कतराते हैं। सरकारों को शहरी नियोजन में साइकिल ट्रैक को प्राथमिकता देनी होगी।इसके साथ ही, समाज को इस संकुचित सोच से भी बाहर निकलना होगा कि साइकिल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गाड़ी नहीं खरीद सकते। साइकिल चलाना पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि एक बेहद जागरूक, समझदार और आधुनिक नागरिक होने की पहचान है। इस विश्व साइकिल दिवस पर हमें केवल औपचारिक संदेश भेजने के बजाय एक छोटा सा व्यावहारिक संकल्प लेना चाहिए। तय करें कि सप्ताह में कम से कम एक या दो दिन हम अपनी गाड़ियों को आराम देंगे और नजदीकी कामों के लिए साइकिल की सवारी करेंगे। जब आपकी साइकिल का पहिया घूमता है, तो देश की सेहत और पर्यावरण का पहिया भी सही दिशा में आगे बढ़ता है।

क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोरा बुलबुला है या वास्तविक चुनौती?

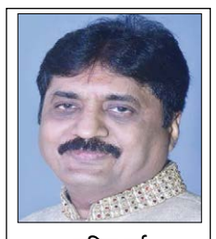

ललित गर्ग

मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिन्होंने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। कृषि क्रांति ने मनुष्य को स्थायित्व दिया, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और श्रम की परिभाषा बदली, सूचना क्रांति ने ज्ञान और संचार की सीमाएं समाप्त कर दीं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की क्रांति मानव इतिहास के एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि, निर्णय क्षमता, रोजगार, सामाजिक संरचना, शासन व्यवस्था और यहां तक कि उसके अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है। यही कारण है कि आज विश्वभर में यह बहस तेज हो रही है कि क्या एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगी या वह धीरे-धीरे मनुष्य के महत्व को ही चुनौती देने लगेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल मशीनों को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन कार्यों को भी करने लगी है जिन्हें लंबे समय तक केवल मनुष्य की विशिष्ट क्षमता माना जाता था। लेखन, चित्र निर्माण, संगीत रचना, रोगों का निदान, न्यायिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय जैसे क्षेत्रों में इसकी बढ़ती उपस्थिति ने अनेक नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि मशीनें सोचने, सीखने और निर्णय लेने लगेंगी तो मनुष्य की विशिष्टता क्या रह जाएगी? यह प्रश्न केवल तकनीकी नहीं, बल्कि दार्शनिक और नैतिक भी है।

मानव अस्मिता का आधार उसकी चेतना, संवेदना, रचनात्मकता और नैतिक विवेक है। एआई के पास विशाल सूचनाओं का भंडार और तीव्र गणनात्मक क्षमता अवश्य है, लेकिन उसके पास अनुभवजन्य चेतना, करुणा, आत्मबोध और मूल्यबोध नहीं है। फिर भी जब मशीनें कविता लिखती हैं, चित्र बनाती हैं और संवाद करती हैं, तब यह भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि वे मनुष्य का स्थान ले सकती हैं। वास्तव में चुनौती यह नहीं है कि मशीनें मनुष्य बन जाएंगी, बल्कि यह है कि कहीं मनुष्य स्वयं मशीनों की तरह व्यवहार करने न लगे। यदि जीवन का प्रत्येक निर्णय गणनात्मक दक्षता और आंकड़ों के आधार पर होने लगे, तो मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य हाशिये पर जा सकते हैं। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या भविष्य में एक नई मानव संरचना का निर्माण होगा? विश्व के अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी चिंतक यह मानते हैं कि आने वाले दशकों में जैविक मनुष्य और डिजिटल तकनीक के बीच की दूरी लगातार कम होगी। मस्तिष्क और कंप्यूटर के प्रत्यक्ष संपर्क, कृत्रिम अंगों, स्मृति-विस्तार तकनीकों और जैव-तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से एक ऐसे युग की कल्पना की जा रही है जहां मनुष्य और मशीन का सम्मिलित स्वरूप विकसित हो सकता है। यह संभावना जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही चिंताजनक भी है। यदि तकनीकी रूप से उन्नत मनुष्य और सामान्य मनुष्य के बीच गहरी खाई बन गई तो सामाजिक असमानता का एक नया रूप सामने आ सकता है।

एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में नियमित और दोहराव वाले कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हो जाएंगे। विश्व की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों ने लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटाई है। किंतु हाल के अनुभव यह भी बताते हैं कि एआई मानव श्रम का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकी है। जटिल निर्णय, नवाचार, मानवीय संबंधों का प्रबंधन और परिस्थितिजन्य विवेक जैसे क्षेत्रों में मनुष्य की भूमिका अभी भी केंद्रीय बनी हुई है। यहीं पर वैश्विक शोध संस्था गार्टनर की हालिया रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है। गार्टनर ने अपनी नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि एआई अब अत्यधिक अपेक्षाओं के शिखर से आगे बढ़कर मोहभंग के चरण में प्रवेश कर रही है। अनेक कंपनियों ने इससे तत्काल आर्थिक लाभ और उत्पादकता में चमत्कारी वृद्धि की उम्मीद की थी, लेकिन वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिले। परियोजनाओं की ऊंची लागत, आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, गलत या भ्रामक उत्तर देने की प्रवृत्ति और स्पष्ट उपयोगिता सिद्ध न कर पाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि लगभग एक-तिहाई परियोजनाएं प्रारंभिक चरण के बाद बंद हो सकती हैं क्योंकि वे अपने निवेश के अनुरूप परिणाम देने में असफल रही हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तत्काल सभी समस्याओं का समाधान बन जाएगी।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि एआई एक अस्थायी बुलबुला है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति के प्रारंभिक चरण में उत्साह और अतिशयोक्ति दोनों मौजूद रहते हैं। बाद में वास्तविक उपयोगिता के आधार पर उसका संतुलित विकास होता है। इंटरनेट के साथ भी यही हुआ था। प्रारंभिक उत्साह के बाद अनेक कंपनियां समाप्त हो गईं, लेकिन इंटरनेट स्वयं विश्व व्यवस्था का आधार बन गया। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है। अतः इसका अतिशयोक्तिपूर्ण महिमामंडन भी उचित नहीं है और इसके शीघ्र समाप्त हो जाने की कल्पना भी यथार्थवादी नहीं है। व्यापार जगत में एआई की भूमिका निरंतर बढ़ेगी। उत्पादन, विपणन, ग्राहक सेवा, वित्तीय विश्लेषण और आपूर्ति प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होगा। इससे कार्यों की गति और दक्षता बढ़ेगी, किंतु साथ ही कार्यबल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। भविष्य में केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्या समाधान, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और भावनात्मक समझ जैसे गुण अधिक महत्वपूर्ण बनेंगे। इसलिए शिक्षा और कौशल विकास की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में भी एआई शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की क्षमता रखती है। नीतिगत विश्लेषण, संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं का संचालन तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। यदि नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़ों का अत्यधिक संग्रह और विश्लेषण होने लगे तो निजता और स्वतंत्रता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए तकनीकी दक्षता और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। सैन्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग सबसे अधिक चिंताजनक माना जा रहा है। स्वायत्त हथियार प्रणालियां, मानव रहित युद्धक उपकरण और लक्ष्य चयन करने वाली मशीनें युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह बदल सकती हैं। यदि किसी मशीन को जीवन और मृत्यु का निर्णय करने की शक्ति मिल जाए तो नैतिक और मानवीय प्रश्न अत्यंत गंभीर हो जाएंगे। इसलिए विश्व स्तर पर ऐसी तकनीकों के नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मानव जीवन सुरक्षित, संतुलित और सार्थक कैसे बना रहे? इसका उत्तर तकनीक के विरोध में नहीं, बल्कि उसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। एआई को मानव जीवन का स्वामी नहीं, सहायक बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, संवेदनशीलता, सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देना होगा। मनुष्य की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, करुणा, सहानुभूति और आध्यात्मिक चेतना ही वे क्षेत्र हैं जिन्हें कोई मशीन प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। साथ ही, वैश्विक स्तर पर ऐसे नियमों और नीतियों की आवश्यकता है जो एआई के विकास को मानव कल्याण की दिशा में नियंत्रित करें। यदि यह तकनीक केवल कुछ शक्तिशाली कंपनियों या राष्ट्रों के हितों तक सीमित रह गई तो असमानता और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास के लिए किया जाए तो यह मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोल सकती है।

अंततः एआई न तो पूर्णतः वरदान है और न ही अनिवार्य रूप से अभिशाप। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसकी दिशा और परिणाम मनुष्य के विवेक पर निर्भर करेंगे। चुनौती मशीनों से नहीं, बल्कि इस बात से है कि क्या मनुष्य अपनी मानवीयता, संवेदनशीलता और नैतिक चेतना को सुरक्षित रख पाएगा। भविष्य का प्रश्न यह नहीं है कि एआई कितनी शक्तिशाली होगी, बल्कि यह है कि मनुष्य कितना सजग, उत्तरदायी और मूल्यनिष्ठ बना रहेगा। यदि मानवता तकनीकी प्रगति और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सकी, तो एआई मानव विकास का नया अध्याय लिखेगी अन्यथा वही तकनीक असंतुलन, असमानता और अस्तित्वगत संकट का कारण भी बन सकती है। यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल सहित कई बदलावों को दी मंजूरी

-अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के कारण क्रिकेट कनाडा को निलंबित किया

दुबई (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने यहां हुई अपनी सालाना आम बैठक में टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के प्रयोग सहित कई अन्य बदलावों को अपनी मंजूरी दे दी है हालांकि ये सभी नियम इस साल अक्टूबर से अमल में लाये जाएंगे। आईसीसी ने कहा है कि खराब रोशनी के दौरान गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आईसीसी ने इसके अलावा टीम के मुख्य कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से रणनीतिक चर्चा करने की अनुमति भी दे दी है। वहीं इस दो दिवसीय बैठक में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

आईसीसी के बयान के अनुसार, टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद का उपयोग दोनों टीमों की सहमति से परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिससे खराब रोशनी की स्थिति में अधिक से अधिक समय तक खेल हो सके। इस नई व्यवस्था के तहत, मैच की शुरुआत पारंपरिक लाल गेंद से होगी, लेकिन यदि दिन के खेल के दौरान रोशनी कम हो जाती है और कुछ ओवर बाकी रह जाते हैं, तो दोनों टीमों की सहमति पर उन शेष ओवरों को फ्लडलाइट्स के दौरान गुलाबी गेंद से पूरा किया जा सकेगा हालांकि भारतीय टीम इस व्यवस्था को स्वीकार करेगी ये अभी पक्का नहीं है क्योंकि भारतीय क्रिकेटर घरेलू हालातों में गुलाबी गेंद से टेस्ट खेलने को लेकर पहले भी तैयार नहीं थे। इसका कारण गुलाबी गेंद से मिलने वाला अधिक सीम मूवमेंट है। वहीं आईसीसी ने खराब रोशनी के कारण खेल में समय के नुकसान को कम करने के लिए मैच अधिकारियों और मैदानों में प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी नई तकनीकों को बेहतर बनाने की भी मंजूरी दी है, इससे किए आईसीसी और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता करेंगे।

खेल नियमों में एक और सुधार करते हुए आईसीसी ने अब मुख्य कोच या उनके प्रतिनिधियों को निर्धारित ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर आकर खिलाड़ियों से बात करने की अनुमति दे दी है। यह सुविधा टी20 क्रिकेट में दी जा रही रणनीतिक टाइम आउट सुविधा के समान है। ये अब टेस्ट क्रिकेट में भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए 15 मिनट के अनिवार्य अंतराल और खेल दोबारा शुरू होने पर बल्लेबाजों के तुरंत तैयार रहने से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दी गयी है। वहीं प्रशासनिक मोर्चे पर, आईसीसी ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों पर क्रिकेट कनाडा को निलंबित करने के साथ-साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के चुनावों की निगरानी के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। गेंदबाजी नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। वैध गेंदबाजी एक्शन पर प्रभावी निगरानी के लिए अब मैदानी अंपायरों को हॉक-आई डेटा तक पहुंच मिलेगी, जिससे वे किसी गेंदबाज के एक्शन की रिपोर्ट करते समय इन आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। लेग साइड वाइड से जुड़े परीक्षण नियम को भी स्थायी रूप से अपनाने की मंजूरी दी गई है। वहीं इसके अलावा महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दी है। इस 10 टीमों के टूर्नामेंट में पांच पूर्ण सदस्य और पांच एसोसिएट सदस्य देश हिस्सा लेंगे, जिनका चयन रैंकिंग और महिला टी20 विश्व कप क्वालीफिकेशन प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आईपीएल 2026 में फ्लाप रहे बुमराह

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल का 2026 सत्र बेहद खराब रहा और वह केवल 4 विकेट ही ले पाये। वहीं उनकी टीम मुम्मई इंडियंस को उम्मीद थी कि वह धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे पर ऐसा नहीं हुआ। बुमराह पूरे सत्र में संघर्ष करते दिखे और उनकी गेंदों पर काफी चौके और छक्के तक लगे। इसके कारण मुम्बई इंडियंस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा।

इस पूरे सत्र में बुमराह 13 मुकाबलों में केवल 4 विकेट ही ले पाये। उनका गेंदबाजी औसत 102.50 का रहा। ये किसी आईपीएल सत्र में 30 से अधिक ओवर फेंकने वाले किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे खराब आंकड़ा है। विकेट लेने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए मशहूर बुमराह एक भी मैच में बल्लेबाजों पर दबाव नहीं डाल सके। वह हर मैच में विकेट के लिए तरसते दिखे। 9 मैचों में तो वह एक भी विकेट नहीं ले पाये। पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच में बुमराह दो विकेट तक नहीं ले पाये।

उनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए, यह उनके आईपीएल करियर का सबसे खराब सत्र रहा। इससे पहले साल 2013 और 2015 में भी उन्होंने केवल 3-3 विकेट ही लिए थे पर तब वह नये गेंदबाज थे। वहीं स बार पूरा सत्र खेलने के बाद भी वह विफल रहे। बुमराह के इस प्रकार असफल होने से उनकी टीम मुंबई इंडियंस भी प्रभावित हुई और केवल चार मैच ही जीतकर अंक तालिका में नवें स्थान पर रही। वहीं बुमराह के लय में नहीं होने से विरोधी टीमों ने मुम्बई के अन्य गेंदबाजों को भी जमकर पीटा। इससे टीम को भी 10 मैचों में हार झेलनी पड़ी।

वैभव पर अध्ययन करेगा आईआईएम इंदौर

इंदौर (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको हैरान करने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिली सफलता से सभी हैरान हैं। प्रशंसकों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना सफल कैसे हो सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) इंदौर ने वैभव के मामले को दुर्लभ मानते हुए अध्ययन का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी उम्र से कहीं बेहतर बल्लेबाजी क्षमता और छक्के मारने की कला के पीछे के रहस्यों का खुलासा करने के लिए खेल, मनोविज्ञान और प्रबंधन के शीर्ष विशेषज्ञ एक साथ काम करेंगे। किसी खिलाड़ी पर आधारित यह देश का पहला अध्ययन होगा जिसमें ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि इतनी कम उम्र के बाद भी वह मैचों के दौरान विपरीत हालातों के बीच भी दबाव में क्यों नहीं आते। वैभव ने आईपीएल सत्र में सबसे अधिक 72 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा था। इसके अलावा 700 से अधिक रन बनाये। वह इस सत्र में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ये अध्ययन केवल वैभव की खेल उपलब्धियों का ही विश्लेषण नहीं करेगी, बल्कि उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारकों को भी गहराई से समझने की कोशिश करेगी जो कम उम्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को आकार देने में सहायक साबित होते हैं। संस्थान का मानना है कि वैभव की क्रिकेट यात्रा के पीछे व्यक्तिगत क्षमता के साथ-साथ कड़ी मेहनत, परिवार का त्याग, समर्पण और मेंटर्स का योगदान भी बेहद अहम रहा है। यह शोध केवल सफलता पर ही केंद्रित नहीं होगा, बल्कि प्रतिभा के विपरीत प्रभाव को भी सामने लायेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि बेहद कम उम्र में मिलने वाली भारी प्रसिद्धि, करोड़ों रुपये के आकर्षक ऑफर और सोशल मीडिया का अनियंत्रित दबाव युवा प्रतिभाओं को विचलित कर देता है। इसके चलते कई खिलाड़ी मानसिक थकान और अत्यधिक अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस अध्ययन के माध्यम से एक ऐसे इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जो कॉर्पोरेट जगत को भी प्रतिभा प्रबंधन का एक बिल्कुल नया और प्रभावी मॉडल प्रदान करेगा।

फीफा विश्वकप 2026, कई नये नियमों के साथ खेला जाएगा

सेन डियागो (एजेंसी)। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले आगामी फीफा विश्वकप 2026 में फुटबॉल के खेल में कई अभूतपूर्व नियम लागू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य मैदान पर खिलाड़ियों के अनुशासन को मजबूत करना और खेल भावना को बढ़ावा देना है। 11 जून से शुरू होने वाले इस वैश्विक टूर्नामेंट में अब खिलाड़ी बहस के दौरान अपना मुंह नहीं छिपा सकेंगे। यदि कोई खिलाड़ी ऐसा करता है, तो उसे तत्काल लाल कार्ड का सामना करना पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण कदम खिलाड़ियों के बीच होने वाले मौखिक दुर्व्यवहार, विशेषकर नस्लीय टिप्पणियों को रोकने के लिए उठाया गया है, जिसने अतीत में खेल की छवि को धूमिल किया है।

मौखिक दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाने के इस कदम के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के नियम तय करने वाली संस्था, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड (आईएफएबी) ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब रेफरी के फैसले के विरोध में मैदान छोड़ने वाले किसी भी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाया जा सकता है। यह नियम उन टीम अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगा जो अपने खिलाड़ियों को विरोध में मैदान छोड़ने के लिए उकसाते हैं। आईएफएबी ने स्पष्ट किया है कि विश्व कप में भाग लेने वाली सभी 48 टीमों को इन सभी संशोधनों के बारे में विस्तार से सूचित किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी न हो।

इन अनुशासनात्मक बदलावों के साथ-साथ, फीफा ने विश्व कप के पीले कार्ड संबंधी नियमों में भी संशोधन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण नॉकआउट मैचों के लिए कम खिलाड़ियों को निलंबन का सामना करना पड़े। नए नियम के अनुसार, विश्व कप के दौरान किसी खिलाड़ी को मिले पीले कार्ड दो बार उसके रिकॉर्ड से हटा दिए जाएंगे। फीफा परिषद ने फीफा विश्व कप 2026 के नियमों में संशोधन करते हुए यह तय किया है कि ग्रुप चरण में मिला कोई भी पीला कार्ड नॉकआउट चरण में मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ है कि नॉकआउट चरण में प्रवेश करने वाले सभी खिलाड़ियों को क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसी तरह, क्वार्टर फाइनल में मिला एक पीला कार्ड अगले मैचों (सेमीफाइनल और फाइनल) के लिए मान्य नहीं होगा।

विश्व कप में इससे पहले यदि किसी खिलाड़ी को दो अलग-अलग मैचों में पीला कार्ड दिखाया जाता था तो उसे एक मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ता था। हालांकि, पिछले टूर्नामेंटों में क्वार्टर फाइनल चरण के बाद एक पीले कार्ड को रद्द कर दिया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि सेमीफाइनल में पीला कार्ड मिलने के कारण कोई भी खिलाड़ी फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच से बाहर न हो। ये नए नियम खिलाड़ियों को बिना अनावश्यक दबाव के बड़े मैचों में अपनी पूरी क्षमता से खेलने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ जाएगा। ये सभी नियम फीफा विश्वकप 2026 को न केवल खेल के लिहाज से बल्कि नैतिकता और निष्पक्षता के दृष्टिकोण से भी एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे।

6 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से शुरु होगा भारतीय टीम का नया कैलेंडर

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19 वां सत्र रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत के साथ ही समाप्त हो गया है। ऐसे में अब इसमें खेल रहे खिलाड़ियों को कोई लंबा ब्रेक मिलने नहीं जा रहा है। इसका कारण है कि भारतीय टीम का नया अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर 6 जून अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से शुरु होगा। भारतीय टीम को अपनी ही धरती पर अफगानिस्तान से सीरीज खेलनी है। भारत दौरे पर आ रही अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम से एक टेस्ट और तीन मैच की एकदिवसीय सीरीज खेलेगी। ऐसे में प्रशंसकों को विराट कोहली और रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी एक बार फिर एकदिवसीय सीरीज में खेलते दिखेंगे।

मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव होने तय, युवाओं की भागीदारी बढेगी

मुम्बई। आईपीएल के 19 वें सत्र में मुंबई इंडियंस की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वह अंक तालिका में 9 वें स्थान पर रही। टीम के स्टार खिलाड़ी भी असफल रहे। इसका अंदाजा इसी से होता है कि सबसे अधिक रन बनाने और विकेट लेने वाले शीर्ष दस-दस खिलाड़ियों में इसका एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं था। आईपीएल के पिछले सत्र में भी टीम का प्रदर्शन खराब रहा था। इस प्रकार लगातार दो सत्र में निराशाजनक सत्र को देखते हुए अब माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव होने तय हैं। फ्रेंचाइजी अब टीम को नए सिरे से तैयार करना चाहती है। इसके तहत टीम में कप्तानी में बदलाव और एक अनुभवी बल्लेबाज को अलग भूमिका देने की योजना शामिल है। आईपीएल 2024 में 10वें और आईपीएल 2026 में 9वें स्थान पर रहने के बाद टीम प्रबंधन अब ये बदलाव करने जा रहा है। टीम में अब युवा खिलाड़ियों की भी भागीदारी बढ़ायी जा सकती है। कप्तान हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर जारी संशय के बीच ही टीम अब नए नेतृत्व विकल्पों की तलाश में है। ये भी कहा जा रहा है कि युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को कप्तान बनाने जाने की संभावना है। युवा तिलक को आईपीएल 2027 से मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी जा सकती है। तिलक पिछले कुछ साल से लगातार मुंबई इंडियंस में शामिल रहे हैं और अपने लगातार प्रदर्शन से टीम प्रदर्शन का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। टीम के भीतर इस बात पर भी चर्चा है कि उन्हें लंबे समय तक नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है। वहीं कप्तानी की दौड़ में दो अन्य अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसमें सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। सूर्या ने आईपीएल 2026 में तीन मैचों में मुंबई की कप्तानी की थी, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में एक मैच में टीम की कप्तानी की थी। ये भी कहा जा रहा है कि फ्रेंचाइजी इन नए बदलावों को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है।

वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए हेटमायर और अल्जारी को शामिल किया

जमैका (एजेंसी)। 3 जून से 8 जून श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए आक्रामक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर और तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की वेस्टइंडीज टीम में वापसी हुई है। ये दोनो ही फिट नहीं होने के कारण पिछले कुछ समय से टीम से बाहर थे। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। ये सीरीज अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप और 2027 विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने के वेस्टइंडीज के अभियान के लिए अहम मानी जा रही है।

हेटमायर को एकदिवसीय टीम में शामिल करना अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप को देखते हुए योजना का एक हिस्सा माना जा रहा है। वह सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे। उनकी आने से टीम की बल्लेबाजी बेहतर होगी। वहीं, तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ जुलाई 2025 से ही पीठ की चोट के कारण बाहर थे और अब लगभग एक साल बाद खेल में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उनके अलावा स्पिनर गुडाकेश मोती को भी टीम में जगह मिली है, जिससे गेंदबाजी आक्रमण बेहतर होने की उम्मीद है।

यह एकदिवसीय सीरीज 3 जून से 8 जून तक जमैका के सबीना पार्क में खेली जाएगी। यह सीरीज वेस्टइंडीज के लिए 2027 वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने के अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन को लेकर टीम पर दबाव होगा। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने श्रीलंका को एक मजबूत और अनुशासित एकदिवसीय टीम करार दिया है। सैमी के अनुसार श्रीलंकाई खिलाड़ी हालातों के अनुसार खेलते हैं। सैमी ने कहा कि इस सीरीज से उनकी टीम को अपने खेल का स्तर जानने और उसमें सुधार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने फील्डिंग में तेजी, बल्लेबाजी में स्पष्ट सोच और गेंदबाजी में लगातार अच्छे प्रदर्शन पर भी जोर दिया है।

कोच सैमी ने कहा कि टीम की रणनीति निडर होकर आक्रामक अंदाज में खेलना रहेगा पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि टीम गलती करेगी। उसका लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन कर अपनी मजबूत पहचान बनाना रहेगा। उनका लक्ष्य घरेलू मैदान पर विरोधी टीमों के लिए कठिनाई पैदा करना रहेगा। उन्होंने जीत के लिए सामूहिक प्रयास और प्रत्येक खिलाड़ी के योगदान को जरुरी बजाया। साथ ही कहा कि टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रहेगी। सैमी ने यह भी कहा कि पिछले 18 महीनों से टीम इसी सोच के साथ काम कर रही है।

एकदिवसीय सीरीज के बाद, दोनों टीमें जमैका में ही तीन टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलेंगी, जिसके बाद यह दौरा एंटीगुआ में दो टेस्ट मैचों के साथ संपन्न होगा।

टीम इस प्रकार है-शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), एकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, शिमरोन हेटमायर, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स और शमर स्प्रिंगर।

नेमार विश्वकप फुटबॉल के पहले मैच में शायद ही खेल पायें

रियो डी जिनेरियो। फीफा विश्व कप 2026 से ठीक पहले ब्राजील को करारा झटका लगा है। उसके स्टार फॉरवर्ड नेमार अब तक अपनी चोट से नहीं उबर पाये हैं। इस कारण अब नेमार मिस्र के खिलाफ 5 जून को होने वाले दूसरे अभ्यास मैच के अलावा विश्वकप फुटबॉल के पहले मैच में भी शायद ही खेल पायें। नेमार की दाहिनी पिंडली की चोट अब तक ठीक नहीं हुई है। इस चोट के कारण ही वह पहले अभ्यास मैच में भी नहीं खेल पाये थे। ब्राजीली फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (सीबीएफ) ने कहा है कि नेशनल कैंप में शामिल हुए नेमार पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले सके और उन्हें अपनी चोटिल पिंडली के लिए अतिरिक्त मेडिकल जांच करवानी पड़ी। मेडिकल जांच और स्कैन से ग्रेड 2 की पिंडली की चोट की पुष्टि हुई है। सीबीएफ के मेडिकल विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह वही चोट है जिसने इस फॉरवर्ड खिलाड़ी को 17 मई से फुटबॉल मैदान से दूर रखा हुआ है। गौरतलब है कि नेमार ने अंतिम बार 17 मई को ब्राजील की नेशनल लीग में सैंटोस की ओर से खेलते हुए कोरीटिबा के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। सीबीएफ के डॉक्टर रोड्रिगो लास्मार ने स्थानीय मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग दो से तीन सप्ताह का समय लग सकता है। इस अनुमानित रिकवरी अवधि को देखते हुए, विश्व कप के शुरुआती मैचों में नेमार की उपलब्धता को लेकर गंभीर संदेह उत्पन्न हो गया है। नेमार बुधवार को रियो डी जनेरियो के बाहर टेरेसोपोलिस में स्थित पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के ट्रेनिंग सेंटर में टीम के बाकी सदस्यों के साथ जुड़े थे। हालांकि, अंतिम मेडिकल जांच के परिणामों का अभी भी इंतजार है पर मौजूदा हालातों को देखते हुए उनके विश्वकप के पहले मैच तक ठीक होने की संभावना नहीं है। वहीं नेमार ने शुरुआत में विश्व कप में अपनी उपलब्धता को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ब्राजील के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले नेमार का करियर पिछले दो सालों से चोटों से बुरी तरह प्रभावित रहा है। उन्होंने ब्राजील के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 17 अक्टूबर 2023 को खेला था। 128 मैचों में 79 गोल कर चुके नेमार का बाहर होना ब्राजील के लिए एक बड़ा नुकसान होगा।

फ्रेंच ओपन 2026 : टियाफो को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अर्नाल्डी

पेरिस। इटली के माटेओ अर्नाल्डी ने 19वें वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस 2026 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। अर्नाल्डी ने पांच घंटे 26 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में टियाफो को 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 से हराया। इसी के साथ ही 25 साल के अर्नाल्डी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी है। इस मुकाबले में दोनो ही खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई। पहले सेट में बराबरी के बाद, टियाफो ने अपनी जबरदस्त वापसी की और तीसरे सेट तक बढ़त बना ली। चौथे सेट में 4-1 की बढ़त के साथ ही टियाफो आगे हो गये पर टाईब्रेक में टियाफो ने आक्रामक खेल दिखाकर अच्छी वापसी की। उन्होंने बैकहैंड शॉट खेलने के बाद ही मैच को पांचवें सेट में पहुंचा दिया। इसके बाद अर्नाल्डी ने अच्छी लय हासिल कर ली। उन्होंने 4-2 की बढ़त बना ली। इसके बाद टियाफो ने एक बार फिर अच्छे फोरहैंड शॉट लगाकर स्कोर 4-4 से बराबरी पर ला दिया। अर्नाल्डी ने अंत में अपने तीसरे मैच अंक को जीतकर यह मुकाबला जीता। अब उनका मुकाबला अपने ही साथी खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी से होगा। इस इस अर्नाल्डी के अलावा इटली के ही बेरेटिनी और फ्लेवियो कोबोली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी है। ये पहली बार है जब एक ही ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में इटली के तीन खिलाड़ी पहुंचे हैं।

फीफा विश्व कप: 'अब सिर्फ खिताब जीतना है', हैरी केन ने इंग्लैंड का लक्ष्य किया साफ

फ्लोरिडा (एजेंसी)। फीफा विश्व कप 2026 से पहले इंग्लैंड की टीम ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कप्तान हैरी केन और मुख्य कोच थॉमस टुचेल ने कहा है कि टीम का एकमात्र लक्ष्य विश्व चैंपियन बनना और जर्सी पर दूसरा सितारा जोड़ना है।

थॉमस टुचेल की अगुआई वाली इंग्लैंड टीम विश्व कप की तैयारियों के लिए फ्लोरिडा पहुंच चुकी है। इंग्लैंड को ग्रुप एल में क्रोएशिया, घाना और पनामा के साथ रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को आर्लिंगटन में क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले से करेगी।

विश्व कप से पहले टीम फ्लोरिडा में मौसम और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की तैयारी कर रही है। हालांकि, बुकायो साका, डेक्लान राइस, नोनी मडुके और एबेरेची एज़े को यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल के बाद अतिरिक्त आराम दिया गया है। वहीं, मार्कस रैशफोर्ड पहले ही मियामी में टीम से जुड़ चुके हैं और गर्म मौसम में विशेष ट्रेनिंग कर रहे हैं।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में टीम के भीतर एकता लगातार मजबूत हुई है, लेकिन अब समय खिताब जीतने का है। केन ने कहा, 'गैरेथ साउथगेट के शुरुआती दौर में हमने टीम को एकजुट बनाने और क्लब क्रिकेट को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने पर काफी काम किया था। हर साल यह भावना और मजबूत होती गई। लेकिन अब उम्मीद सिर्फ एक है–फिनिश लाइन पार करना और ट्रॉफी जीतना।'

इंग्लैंड टीम की आधिकारिक डॉक्यूमेंट्री 'बिल्डिंग द ड्रीम' में भी दिखाया गया कि टुचेल ने खिलाड़ियों के साथ अपनी पहली बैठक में ही विश्व कप जीतने के लक्ष्य पर खुलकर चर्चा की थी।

टुचेल ने खिलाड़ियों से कहा, 'हम यहां क्यों हैं, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हम विश्व चैंपियन बनना चाहते हैं। हम अपनी जर्सी पर दूसरा सितारा जोड़ना चाहते हैं। मेरे लिए यह जरूरी है कि हम इस लक्ष्य के बारे में खुलकर बात करें। हमारा मिशन और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है।'

टुचेल का मानना है कि सिर्फ प्रतिभा के दम पर विश्व कप नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में टीम की एकजुटता और आपसी विश्वास सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। यह केवल फुटबॉल, रणनीति या सेट-पीस की बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में टीम का माहौल और खिलाड़ियों के बीच का रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण होता है।'

टुचेल ने एक विश्व कप विजेता खिलाड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि क्वार्टर फाइनल और फाइनल के बीच फर्क सिर्फ खेल का नहीं, बल्कि टीम के भीतर बने भाईचारे का होता है। उन्होंने कहा, 'जब खिलाड़ी एक परिवार और भाईचारे की तरह जुड़ जाते हैं, तब वे एक-दूसरे के लिए सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। यही भावना किसी टीम को चैंपियन बनाती है।' इंग्लैंड ने अब तक सिर्फ एक बार विश्व कप का खिताब जीता है। ऐसे में टुचेल और केन की नजरें इतिहास रचते हुए देश को दूसरा विश्व कप दिलाने पर टिकी हैं।

संक्षिप्त डायरी

सोशल मीडिया बना पति-पत्नी विवाद का मुख्य कारण, नालंदा में दर्ज हो रहे सैकड़ों केस

पटना (एजेंसी) व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइटें जहां लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों में रिश्तों की दरार की वजह भी बनती जा रही हैं. नालंदा जिले में बढ़ते दांपत्य विवादों के पीछे सोशल मीडिया एक बड़ा कारण बनकर उभरा है. छोटी-छोटी गलतफहमियां अब महिला थाना, महिला हेल्पलाइन और फैमिली कोर्ट तक पहुंच रही हैं. (कंचन कुमार) फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइटें जहां लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों में रिश्तों की दरार की वजह भी बनती जा रही हैं. नालंदा जिले में बढ़ते दांपत्य विवादों के पीछे सोशल मीडिया एक बड़ा कारण बनकर उभरा है. छोटी-छोटी गलतफहमियां अब महिला थाना, महिला हेल्पलाइन और फैमिली कोर्ट तक पहुंच रही हैं. हर महीने 250 से ज्यादा पति-पत्नी विवाद पहुंच रहे थाने और कोर्ट फैमिली कोर्ट, महिला थाना और महिला हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि जिले में हर माह 251 से 322 दांपत्य विवाद दर्ज हो रहे हैं. यानी औसतन प्रतिदिन दो से तीन नए मामले सामने आ रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे परामर्श केंद्रों पर भी दबाव बढ़ा है. सबसे ज्यादा विवाद शिक्षित और नौकरीपेशा दंपतियों में आंकड़ों के अनुसार 80 प्रतिशत से अधिक मामले शिक्षित और नौकरीपेशा दंपतियों से जुड़े हैं. आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद कई परिवारों में विवाह के पांच से दस वर्ष के भीतर रिश्ते संकट में पहुंच रहे हैं. विशेषज्ञ बदलती जीवनशैली और बढ़ती व्यक्तिगत अपेक्षाओं को इसकी बड़ी वजह मानते हैं. लाइक, कमेंट और चैट से बढ़ रहा अविश्वास विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट, फ्रेंड रिक्वेस्ट और निजी चैट को लेकर पति-पत्नी के बीच संदेह बढ़ रहा है. कई मामलों में मोबाइल की जांच, कॉल डिटेल देखने और निजी संदेश पढ़ने की आदत रिश्तों में तनाव पैदा कर रही है. संवाद की कमी होने पर यही तनाव बड़े विवाद में बदल जाता है. संयुक्त परिवार से दूरी भी बन रही विवाद की वजह दांपत्य विवादों में एक बड़ा कारण संयुक्त परिवार से अलग रहने की इच्छा भी सामने आ रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 62 प्रतिशत मामलों में पति-पत्नी के बीच अलग रहने को लेकर विवाद होता है. परिवार और रिश्तों को लेकर बदलती सोच का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है. दहेज के आरोपों से बढ़ रही कानूनी जटिलताएं दांपत्य विवादों के लगभग 82 प्रतिशत मामलों में दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं. जांच में कुछ आरोप सही साबित होते हैं, जबकि कई मामलों में उनकी पुष्टि नहीं हो पाती. इससे कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है और दोनों पक्षों के बीच दूरियां और बढ़ जाती हैं. बढ़ती अपेक्षाएं भी रिश्तों पर डाल रही दबाव विशेषज्ञों का कहना है कि आज अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से मजबूत और नौकरीपेशा वर को प्राथमिकता देते हैं. लेकिन शादी के बाद जब जीवनशैली, सोच और व्यवहार में सामंजस्य नहीं बन पाता, तो रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है. कई बार अवास्तविक अपेक्षाएं भी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती हैं. टूटते रिश्तों की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे बच्चे दांपत्य कलह का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ रहा है. तनावपूर्ण माहौल उनके मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित करता है.

समस्तीपुर और पटना के बीच गंगा नदी पर बन रहा पीपा पुल, घंटों की दूरी बस मिनटों में होगी तय

पटना (एजेंसी) समस्तीपुर और पटना के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल बन रहा है. इस पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है. इस पुल के तैयार हो जाने के बाद समस्तीपुर से पटना के बीच घंटों की दूरी सिर्फ मिनटों में ही पूरी की जा सकेगी. इस परियोजना में कुछ एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है. बिहार में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई सड़क और पुल परियोजनाओं पर काम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में समस्तीपुर और पटना के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल बनाया जा रहा है. इस पुल के बनने से दियारा इलाके के हजारों लोगों को फायदा मिल सकेगा. काफी लंबे समय से लोग इस पुल के बनने का इंतजार कर रहे थे. समस्तीपुर से पटना का सफर मिनटों में होगा पूरा बताया जा रहा है कि पीपा पुल के निर्माण कार्य में तेजी ला दी गई है. जल्द ही इसे पूरा करने को लेकर दिन-रात काम किया जा रहा है. समस्तीपुर से पटना के बीच की दूरी तय करने में फिलहाल लगभग 2 घंटे का समय लगता है. लेकिन पीपा पुल के बन जाने के बाद समस्तीपुर से पटना के बॉर्डर वाले इलाकों तक पहुंचने में सिर्फ आधे घंटे का ही समय लग सकोगा. पीपा पुल का दिखने लगा है स्ट्रक्चर जिस तरह से पीपा पुल का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है, पहले सिर्फ ड्रम या फिर अन्य सामान दिखते थे. लेकिन अब पीपा पुल का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक, पीपा पुल के लिए लगाए गए ड्रमों के ऊपर लोहे के चैनल और प्लेट लगाए जा रहे हैं. पुल मजबूत रहे, इसे ध्यान में रखते हुए मजबूत लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है. लगभग 8 एमएम मोटी लोहे की प्लेटें बिछाई जा रहीं हैं. सभी काम पूरा होने के बाद इस पर गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा. पुल के निर्माण में ली जा रही एक्सपर्ट की सलाह जानकारी के मुताबिक, पीपा पुल के निर्माण में एक्सपर्ट की सलाह भी ली जा रही है. राज्य के दूसरे जिले जैसे कि पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, और सहरसा के एक्सपर्ट इस काम में लगे हुए हैं. साथ ही निर्माण कार्य भी अनुभवी कारीगर की ओर से ही किया जा रहा है. इसके बन जाने के बाद लोगों को खासकर बारिश के दिनों में राहत मिल सकेगी. फिलहाल दियारा इलाके के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन पीपा पुल के बनने से लोगों को खास सुविधा मिल सकेगी.

बिहार में अब नहीं होगी बालू की कमी, 161 नए घाटों से जल्द शुरू होगा खनन, निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार

पटना (एजेंसी) बिहार में जल्द ही 161 नए बालू घाटों से खनन शुरू होने वाला है. इससे बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और निर्माण कार्यों के लिए लोगों को उचित कीमत पर आसानी से बालू मिल सकेगा. बिहार में निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता जल्द और बेहतर होने वाली है. राज्य सरकार ने पीला बालू के 107 और उजला बालू के 54 नए घाटों की बंदोबस्ती पूरी कर ली है. अब इन घाटों से जल्द खनन शुरू करने की तैयारी चल रही है. कई जिलों को मिलेगा फायदा जिन नए घाटों से खनन शुरू होना है, उनमें भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, गया और जमुई जैसे जिले प्रमुख हैं. इन जिलों में खनन शुरू होने से स्थानीय स्तर पर बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को निर्माण कार्यों के लिए आसानी से बालू मिल सकेगा. 311 पीला और 89 उजला बालू घाट होंगे सक्रिय वर्तमान में राज्य में पीला बालू के लगभग 204 घाटों और उजला बालू के 35 घाटों से खनन हो रहा है. नए घाटों के शुरू होने के बाद पीला बालू के सक्रिय घाटों की संख्या बढ़कर 311 हो जाएगी. वहीं उजला बालू के 89 घाटों से खनन शुरू हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि घाटों की संख्या बढ़ने से बाजार में बालू की आपूर्ति बेहतर होगी और कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. कई घाटों की नीलामी अभी बाकी खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार राज्य में पीला बालू के कुल 466 घाट चिन्हित हैं. इनमें से अब तक 311 घाटों की ही बंदोबस्ती हो सकी है, जबकि 155 घाटों की प्रक्रिया अभी बाकी है. वहीं उजला बालू के कुल 541 घाट हैं. इनमें से 452 घाटों की नीलामी अभी तक नहीं हुई है. विभाग ने इन सभी घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं.

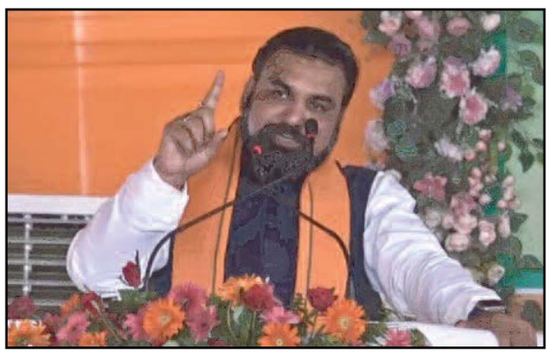

सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं, नेतृत्व कहेगा तो 24 घंटे में छोड़ दूंगा: सम्राट चौधरी

पटना (एजेंसी) बिहार में बंगला विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है और जिस दिन पार्टी व नेतृत्व कहेगा, वह 24 घंटे के भीतर झोला उठाकर अपना सरकारी घर छोड़ देंगे. बिहार में सरकारी बंगले को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. शेखपुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि वह पद और सरकारी आवास से मोह रखने वालों में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जिस दिन पार्टी और नेतृत्व कहेगा कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, वह 24 घंटे के भीतर सरकारी आवास छोड़कर अपने निजी घर चले जाएंगे. सम्राट चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है. 24 घंटे में झोला उठाकर निकल जाऊंगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं, किसी सरकारी घर या सुविधा के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं समाप्त होता है, सम्राट चौधरी 24 घंटे के भीतर अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पद और आवास स्थायी नहीं होते, बल्कि जनता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है. सरकारी आवास किसी की बपौती नहींसम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वह सरकारी आवास पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बाहर लिख दिया जाए कि यह लोकसेवक का आवास है. यह जनता की सेवा का केंद्र है, किसी की निजी संपत्ति नहीं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारी आवास और सरकारी सुविधाएं नियमों के तहत मिलती हैं और समय आने पर उन्हें छोड़ना भी पड़ता है. मैं कई पदों पर रहा, लेकिन घर का मोह नहीं रखा मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वह पिछले कई वर्षों में मंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. इसके बावजूद उन्होंने लंबे समय तक अपने निजी घर में रहना पसंद किया. उन्होंने बताया कि राजनीति के सफर में अब तक वह कई सरकारी आवास बदल चुके हैं. आज जिस घर में वह रह रहे हैं, वह उनका ग्यारहवां सरकारी आवास है. बिना नाम लिए साधा निशाना अपने संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकारी घरों से इतना लगाव रखते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने आवास की चिंता रहती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को बेटे के लिए अलग घर और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, जबकि उनकी सरकार जनता की सेवा को प्राथमिकता देती है. जनता की भलाई के लिए राजनीति मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल जनता के हित में काम करना है. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन और विकास की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और जनप्रतिनिधियों को हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनता की भलाई और राज्य के विकास के लिए लगातार काम करती रहेगी.

ऑनलाइन पोर्टल पर बिहार की सरकारी जमीन के बारे में कैसे मिलेगी जानकारी? जानिए प्रोसेस

पटना (एजेंसी) बिहार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं. इसके लिए बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है. ऐसे में बड़ा डिजिटल अभियान शुरू किया गया है. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अंचल अधिकारी और लोग सरकारी जमीन की पहचान कर सकेंगे. बिहार में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है.

ताकि उस जमीन को सरकारी लोगों की सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सके. सरकारी जमीन की सुरक्षा और इससे अवैध कब्जा हटाने के लिए एक डिजिटल अभियान शुरू किया गया है. बिहार सर्वेक्षण कार्यालय की उप निदेशक मोना झा की ओर से सभी जिलों के डीएम को एक लेटर भेजा गया है.

सभी डीएम को दिया गया ये आदेश लेटर के जरिए सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है कि सरकारी जमीन से जुड़े जमाबंदियों को ऑनलाइन चिह्नित कर प्रदर्शित किया जाए. जानकारी के मुताबिक, ह्यबिहार भूमि पोर्टलह्न में ही ई-जमाबंदी मॉड्यूल में खास प्रवधान किया गया है. इसके जरिए किसी भी अंचल के अधिकारी यह जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन सी जमीन सरकारी है. अंचल अधिकारी ऐसे ले सकेंगे पोर्टल से जानकारी सरकारी जमीन की पहचान के लिए पहले अंचल अधिकारी को ीमॉड्यूल पर लॉग इन करना होगा. फिर रिपोर्टिंग मेनू में जाना होगा. यहां सर्च गवर्नमेंट लैंड पर क्लिक करना होगा. इसके बाद कई जानकारी देनी होगी जैसे कि जिला, हलका, मौजा, वर्तमान जमाबंदी समेत सभी जानकारी देने के बाद सर्च पर जाकर क्लिक करना होगा. इसके बाद सरकारी जमीन और उनसे जुड़ी जमाबंदियों की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी.

सरकार की नई व्यवस्था से होने वाले फायदेबिहार सरकार की इस नई व्यवस्था से काफी फायदा हो सकेगा. सभी काम पारदर्शी होने की वजह से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आ सकेगी. खासकर जो जमीन माफिया हैं, वे लोगों को धोखा देकर जमीन नहीं बेच सकेंगे.

इसके अलावा सरकार के साथ-साथ आम लोगों के पास भी पूरा डेटा ऑनलाइन ही मौजूद होगा. इससे किसी तरह के फर्जीवाड़े में कमी आ सकेगी.

मलमास मेला ड्यूटी पर प्रशासन सख्त, बिहारशरीफ से राजगीर के लिए शुरू हुई विशेष बस सेवा

पटना (एजेंसी) राजगीर मलमास मेला 2026 में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष बस सेवा शुरू कर दी है. अब प्रतिदिन सुबह 5 बजे समाहरणालय परिसर, बिहारशरीफ से राजगीर मेला क्षेत्र के लिए बस रवाना होगी. (कंचन कुमार) राजगीर मलमास मेला 2026 में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष बस सेवा शुरू कर दी है. अब प्रतिदिन सुबह 5 बजे समाहरणालय परिसर, बिहारशरीफ से राजगीर मेला क्षेत्र के लिए बस रवाना होगी. प्रशासन का उद्देश्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना है. जिलाधिकारी के निर्देश पर शुरू हुई व्यवस्था जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने यह विशेष व्यवस्था लागू की है. अधिकारियों का मानना है कि नियमित परिवहन सुविधा मिलने से ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को समय पर मेला क्षेत्र पहुंचने में सहूलियत होगी. औचक निरीक्षण में खुली थी लापरवाही की पोल हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित काउंटरों से अनुपस्थित पाए गए थे. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कारणों की जांच कराई, जिसमें परिवहन संबंधी समस्याएं सामने आईं. निजी वाहन नहीं होने से हो रही थी परेशानी जांच में पता चला कि बिहारशरीफ से राजगीर आने-जाने के लिए कई कर्मियों के पास निजी वाहन नहीं थे. वहीं सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता के कारण उन्हें समय पर ड्यूटी स्थल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद बड़ा फैसला सूत्रों के अनुसार मलमास मेला ड्यूटी से एक दर्जन से अधिक कर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने के बाद प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया. इसी के तहत विशेष बस सेवा शुरू की गई है

बिहार में अब नहीं होगी बालू की कमी, 161 नए घाटों से जल्द शुरू होगा खनन, निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार

पटना (एजेंसी) बिहार में जल्द ही 161 नए बालू घाटों से खनन शुरू होने वाला है. इससे बाजार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और निर्माण कार्यों के लिए लोगों को उचित कीमत पर आसानी से बालू मिल सकेगा. बिहार में निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता जल्द और बेहतर होने वाली है. राज्य सरकार ने पीला बालू के 107 और उजला बालू के 54 नए घाटों की बंदोबस्ती पूरी कर ली है. अब इन घाटों से जल्द खनन शुरू करने की तैयारी चल रही है. कई जिलों को मिलेगा फायदा जिन नए घाटों से खनन शुरू होना है, उनमें भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, गया और जमुई जैसे जिले प्रमुख हैं. इन जिलों में खनन शुरू होने से स्थानीय स्तर पर बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को निर्माण कार्यों के लिए आसानी से बालू मिल सकेगा. 311 पीला और 89 उजला बालू घाट होंगे सक्रिय वर्तमान में राज्य में पीला बालू के लगभग 204 घाटों और उजला बालू के 35 घाटों से खनन हो रहा है. नए घाटों के शुरू होने के बाद पीला बालू के सक्रिय घाटों की संख्या बढ़कर 311 हो जाएगी. वहीं उजला बालू के 89 घाटों से खनन शुरू हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि घाटों की संख्या बढ़ने से बाजार में बालू की आपूर्ति बेहतर होगी और कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. कई घाटों की नीलामी अभी बाकी खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार राज्य में पीला बालू के कुल 466 घाट चिन्हित हैं. इनमें से अब तक 311 घाटों की ही बंदोबस्ती हो सकी है, जबकि 155 घाटों की प्रक्रिया अभी बाकी है. वहीं उजला बालू के कुल 541 घाट हैं. इनमें से 452 घाटों की नीलामी अभी तक नहीं हुई है. विभाग ने इन सभी घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं. निर्माण क्षेत्र को मिलेगी राहत अधिकारियों का मानना है कि अधिक घाटों से खनन शुरू होने पर बालू की कमी की समस्या कम होगी. इससे आम लोगों, मकान बनाने वालों और निर्माण एजेंसियों को उचित दर पर बालू उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है.

बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा ड्राइविंग स्कूल, परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा नया गाइडलाइन

पटना (एजेंसी) बिहार में ड्राइविंग स्कूलों के लिए नया गाइडलाइन जारी होने वाला है. परिवहन विभाग की ओर से पोर्टल बनाया जा रहा है. नये गाइडलाइन के मुताबिक, बिना रजिस्ट्रेशन राज्य में ड्राइविंग स्कूल नहीं चलेंगे. पटना से प्रह्लाद कुमार की रिपोर्ट अब सार्वजनिक सड़क पर मोटर ड्राइविंग नहीं सीख पायेंगे. ड्राइविंग सीखाने वाली एजेंसी को जगह का ब्योरा बताना होगा. इसके साथ ही राज्यभर में चल रहे सभी ड्राइविंग स्कूलों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ऐसे स्कूलों के लिए एनआईसी के माध्यम से पोर्टल तैयार कर रहा है, जहां सभी ड्राइविंग स्कूलों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जानकारी के मुताबिक, इन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया जायेगा, ताकि इन स्कूलों से ट्रेनिंग लेने वाले वाहन चालकों का प्रमाण पत्र मान्य हो सकें. विभागीय समीक्षा में पाया गया कि ड्राइविंग स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन इन स्कूलों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. बिना लाइसेंस लिए सड़क पर सीखने वालों पर होगी कार्रवाई ड्राइविंग स्कूलों में ट्रेनिंग मामले में विभाग नियमों को सख्त बनाया जायेगा. विभाग गाइडलाइन जारी करने जा रहा है, जिसमें ड्राइविंग स्कूल रजिस्ट्रेशन के बाद कहां ट्रेनिंग देंगे, इसका पूरा ब्योरा विभाग को देना होगा. खुली सड़कों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रेनिंग नहीं कराया जायेगा. साथ ही ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियों पर अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है, तो उस व्यक्ति के पास लाइसेंस अनिवार्य रूप से रहना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर ट्रेनिंग लेने और ट्रेनिंग देने दोनों पर कार्रवाई की जायेगी. ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी व्यवस्था विभागीय अधिकारियों के मुताबिक निजी तौर पर हर दिन खुल रहे ड्राइविंग स्कूल को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए राज्य भर में विभाग पोर्टल की व्यवस्था करेगा. अगर कोई ड्राइविंग स्कूल के प्रबंधक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम नहीं है तो वह जिला के डीटीओ कार्यालय से भी रजिस्ट्रेशन करा पायेगा. इसके लिए व्यवस्था की जायेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो.

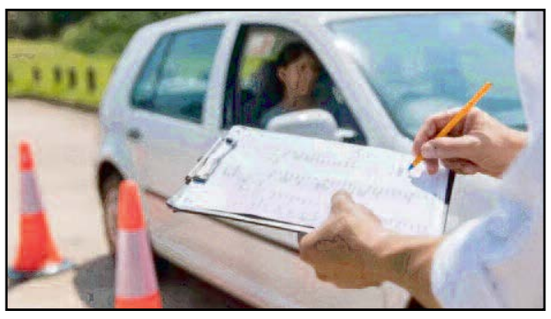

पटना सहित बिहार में 10 लाख से ज्यादा आय वालों पर गैस सब्सिडी बंद, लाखों उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज

पटना (एजेंसी) पटना सहित बिहार में 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए लाखों लोगों को अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा है. पटना सहित बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के बीच हड़कंप मच गया है. तीनों सरकारी गैस कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए लाखों उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा है. 10 लाख से ज्यादा आय वालों की सब्सिडी होगी बंद तेल कंपनियों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं या उनके परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें गैस सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जाएगा. ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 7 दिन का समय दिया गया है, जिसमें वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. लाखों उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा मैसेज सूत्रों के अनुसार पटना सहित पूरे बिहार में 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को यह अलर्ट मैसेज भेजा जा रहा है. मैसेज में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो सब्सिडी स्वतः बंद कर दी जाएगी. 234.65 लाख उपभोक्ता आए रडार पर बिहार में कुल 234.65 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं. इनमें आईओसी के 110.57 लाख, बीपीसीएल के 57.05 लाख और एचपीसीएल के 67.01 लाख उपभोक्ता शामिल हैं. अकेले पटना में भी 13 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ता बताए जा रहे हैं. सरकारी कर्मचारी और कारोबारी प्रभावित होंगे इस नई व्यवस्था से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कारोबारी और उच्च आय वर्ग के उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे. सरकार का उद्देश्य केवल पात्र और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी देना है. मृत उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी जांच के दायरे में गैस कंपनियों ने मृत उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की भी जांच शुरू कर दी है. आधार डाटाबेस के जरिए ऐसे कनेक्शनों की पहचान की जा रही है जिनके धारक अब जीवित नहीं हैं. 30 दिन में ट्रांसफर नहीं तो कनेक्शन बंद कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को 30 दिन के भीतर कनेक्शन को वैध सदस्य के नाम ट्रांसफर कराना होगा, अन्यथा कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा. टोल फ्री नंबर से दर्ज करा सकते हैं शिकायत यदि किसी उपभोक्ता को इस कार्रवाई पर आपत्ति है तो वे टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं. सरकारी स्तर पर चल रही है प्रक्रिया गैस कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही है

मामले पर रामकृपाल यादव बोले- पीएम मोदी ने खुद लिया है संज्ञान, राबड़ी आवास विवाद पर भी बोले बिहार के मंत्री

पटना (एजेंसी) परीक्षा में गड़बड़ी और राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार दोनों मामलों में नियम और कानून के तहत काम कर रही है. बिहार और देश की राजनीति में इस समय दो मुद्दों को लेकर बहस तेज है. पहला मामला परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों का है, जबकि दूसरा पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सरकारी आवास और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है. इन दोनों मुद्दों पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में जहां-जहां कमियां सामने आई हैं, उन्हें दूर करने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना प्रधानमंत्री ने लिया है संज्ञान मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे मामले पर नजर रखी है. उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो सभी पहलुओं की जांच कर रही है. रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग किए जाने पर रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह केवल आरोप लगाने में जुटा हुआ है.राबड़ी देवी के बंगले पर भी रखी सरकार की बात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर उठे विवाद पर भी मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और सुरक्षा देने के लिए स्पष्ट सरकारी नियम बने हुए हैं. रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में जो भी फैसले लिए जाते हैं, वे निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही होते हैं. किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाता. सुरक्षा और आवास को लेकर तय है प्रोटोकॉल मंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा और आवास उपलब्ध कराने के लिए एक तय प्रोटोकॉल है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व करते रहे हैं. ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर कई फैसले लिए जाते हैं, जिन पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन सरकार नियमों के अनुसार ही काम करती है

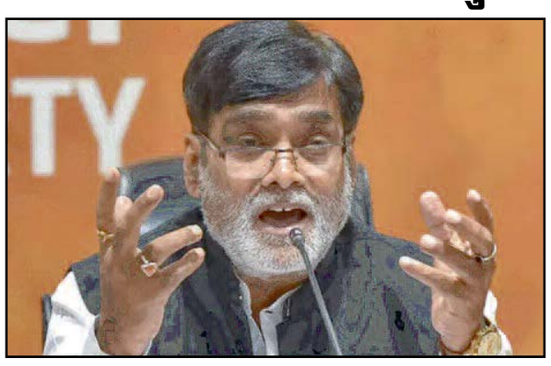

फरहाना भट्ट ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल फैसले के बारे में बात की

सलमान खान के रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की चर्चित कंटेस्टेंट रहीं फरहाना भट्ट ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल और भावुक फैसले के बारे में खुलकर बात की।

एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपने सपनों को अहमियत देती हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया और उनसे कहा कि वे उन्हें सार्वजनिक रूप से बेदखल कर दें। फरहाना ने यह कदम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठाया। कश्मीर की रहने वाली फरहाना भट्ट को 'बिग बॉस 19' में अपने बेबाक और निडर व्यक्तित्व के कारण खूब चर्चा मिली। शो के दौरान उनकी अभद्र भाषा पर काफी ट्रोलिंग भी हुई। शो के बाद फरहाना सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं। अब वह रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। फरहाना ने अपनी भावनात्मक उथल-पुथल का जिक्र करते हुए बताया कि खून के रिश्तों यानी अपनों से उम्मीदें रखना स्वाभाविक है लेकिन जब सबसे मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता तो फैसला लेना और भी कठिन हो जाता है। खास बातचीत में फरहाना ने बताया, 'मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम यह था कि मैंने खुद को अपने करीबी खून के रिश्तों से पूरी तरह अलग कर लिया। मैंने उनसे कह दिया कि आप सार्वजनिक रूप से ऐलान कर सकते हैं कि 'वह हमारी नहीं है' या उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है।'

फरहाना ने बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। परिवार से दूरी का फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अकेले लड़ने की हिम्मत जुटाई। फरहाना ने बताया, 'जब आपके आसपास सच में कोई नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी मां होती हैं और आप परिवार से रिश्ता तोड़ रहे होते हैं, तो उस पल आप खुद को पूरी तरह अकेलेपन के हवाले कर देते हैं। मैंने तय किया कि मैं अकेली रहूंगी, लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम था।'

एक्टर होना हर बार नई दुनिया में कदम रखने जैसा है

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी फिल्म 'सिस्टम' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच, फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अभिनय और अपने किरदार को लेकर आईएएनएस से बात करते हुए कई दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि एक अभिनेता का काम बाहर से देखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, ''जब कोई एक्टर किसी नए किरदार को निभाता है, तो वह उसकी पूरी दुनिया में कदम रखता है। हर फिल्म और हर रोल एक अलग जिंदगी की तरह होता है, जिसमें नियम, रिश्ते और परिस्थितियां बिल्कुल नई होती हैं। मुझे अभिनय हमेशा रोमांचक लगता है, क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने और महसूस करने का मौका मिलता है।'' सोनाक्षी ने कहा कि किसी भी प्रोफेशन को बाहर से देखकर पूरी तरह समझना मुश्किल होता है। जैसे वकील या डॉक्टर की दुनिया को समझना आसान नहीं होता, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यह सिर्फ वही लोग जानते हैं जो खुद उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों। लोग अक्सर सोचते हैं कि फिल्में सिर्फ ग्लैमर और कैमरे तक सीमित होती हैं, लेकिन असल में एक फिल्म के पीछे बहुत सारे लोग, मेहनत और तैयारी होती है, जो मिलकर एक कहानी को आकार देती है।''

फिल्म 'सिस्टम' में सोनाक्षी सिन्हा एक वकील का किरदार निभा रही हैं, जिसका नाम नेहा राजवंश है। उसके पिता रवि राजवंश उन्हें खुद को साबित करने की चुनौती देते हैं और सामने एक शर्त रखते हैं, जिसमें 10 केस जीतने की बात कही जाती है। इस शर्त को पूरा करने के लिए वह हाई-प्रोफाइल केस लड़ती हैं। इस दौरान उसकी मुलाकात अभिनेत्री ज्योतिका के किरदार सारिका रावत से होती है। वह एक स्टेनोग्राफर हैं। फिल्म 'सिस्टम' को पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। अश्विनी अय्यर तिवारी ने हरमन बावेजा, अरुण सुकुमार और तस्नीम लोखंडवाला के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है।

रणदीप ने 'छावा' में ठुकराया औरंगजेब का रोल

एक्टर रणदीप हुड्डा लक्ष्मण उतेकर की अपकमिंग फिल्म 'ईथा' में श्रद्धा कपूर के साथ मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस बीच उन्होंने बताया कि उन्हें 2025 की हिट फिल्म 'छावा' में मुगल बादशाह औरंगजेब का रोल ऑफर हुआ था। इस फिल्म में विक्की कौशल लीड रोल में थे। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। हुड्डा ने बताया कि उन्होंने औरंगजेब के रोल को ठुकरा दिया था। बाद में यह रोल अक्षय खन्ना ने निभाया। औरंगजेब का रोल ठुकराने की वजह बताते हुए रणदीप ने 'जूम' को बताया कि जब डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने उनसे 'छावा' के लिए संपर्क किया था, तब वे मानसिक रूप से सही स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि उस समय उनका वजन बहुत कम था और उन्होंने अपना सिर मुंडवा रखा था। उन्होंने उस वक्त 'सावरकर' की शूटिंग पूरी की थी। उन्होंने कहा 'मैं एक केस से गुजर रहा था और उस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई पेचीदा मसले थे। मैं उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। ऐसे में जब मेरे पास यह प्रोजेक्ट (ईथा) मेरे सामने आया, तो मुझे यह काफी लुभावना लगा।'

'छावा' 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक संभाजी के जीवन पर आधारित थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'छावा' का बजट 130 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस पर 804 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया था।

फिर हिंदी सिनेमा में वापसी करना चाहती हैं स्नेहा उल्लाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल ने हाल ही में अपने करियर और निजी जिंदगी को लेकर कई दिलचस्प बातें शेयर कीं। साथ ही ऐश्वर्या राय से उनकी तुलना होने पर भी खुलकर चर्चा की।

मजबूरी में रखा था फिल्मों में कदम

अल्फेनियन स्टूडियोज को दिए इंटरव्यू में स्नेहा ने बताया कि जब उन्हें फिल्म का ऑफर मिला, तब वो सिर्फ 17 साल की थीं और हाल ही में कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसी दौरान उनकी मां कैंसर का इलाज करवा रही थीं। घर का माहौल काफी उदास था। ऐसे में उन्होंने ये फिल्म सिर्फ इसलिए साइन की ताकि परिवार का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस मुश्किल समय से हट सके। उन्होंने कहा, 'मां को घूमना-फिरना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इस ऑफर को हां कह दिया। उस फैसले ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, चाहे मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी थी या नहीं।' इसी बातचीत में स्नेहा ने ऐश्वर्या राय बच्चन से होने वाली तुलना पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनी थीं, तभी से लोग कहते थे कि दोनों की शक्ल काफी मिलती है। बाद में सलमान खान के साथ डेब्यू करने की वजह से लोगों ने अलग-अलग बातें बनानी शुरू कर दीं, लेकिन मैं उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए इन चीजों का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

सिनेमा में वापसी करना चाहती हैं एक्ट्रेस

वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड के बाद स्नेहा ने साउथ फिल्मों में भी काम किया। अब वो धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही हैं। स्नेहा का कहना है कि वो इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हैं और अब उन्हें साफ पता है कि वो किस तरह की एक्ट्रेस बनना चाहती हैं।

'ब्राउन' में सस्पेंस और अंधेरे से भरी दुनिया में दिखेंगी करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर की आगामी वेब सीरीज 'ब्राउन' का टीजर जारी कर दिया गया है। जी5 पर रिलीज होने वाली इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर में करिश्मा अब तक के अपने सबसे अलग और इंटेंस अवतार में नजर आएंगी। टीजर में करिश्मा कोलकाता पुलिस की अफसर रीटा ब्राउन की भूमिका निभाती दिख रही हैं, जो अपने निजी संघर्षों और शहर में हो रहे खौफनाक अपराधों से जूझती नजर आती हैं। कोलकाता की रहस्यमयी और अंधेरी पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष और अपराध की गहरी परतों को दिखाने वाली कहानी है। टीजर में करिश्मा का रफ और बिना ग्लैमर वाला लुक है। इस वेब सीरीज का निर्देशन अभिनय देव ने किया है।

कई बार सेल्फ डाउट से गुजरी हूं

आईएएस की तैयारियों में मसरूफ रूबीना जब मिस शिमला बनीं, तो उनके जीवन की धारा मुड़ गई। हालांकि उनके पिता डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर और लेखक थे, तो भाषा और कला उनके खून में थी। सेब का बिजनेस करने वाले मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली रूबीना हिमाचल के एक छोटे-से कस्बे से मुंबई आईं और छोटे पर्दे पर छा गईं। अपने करियर में हर तरह का काम कर चुकी रूबीना आज दो जुड़वा बेटियों की प्राउड मदर हैं। इन दिनों वे चर्चा में हैं अपने नए रिएलिटी शो द वार्ड से। उनसे एक खास बातचीत।

आम तौर पर हमारे समाज में बेटे को घर का चिराग और वंश को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। रूबीना ने स्वयं इस मानसिकता को अपने घर में महसूस किया है। वे कहती हैं, 'मुझसे आज भी मेरे गांव वाले पूछते हैं कि रूबीना तुम बेटे के लिए ट्राई करने वाली हो, तो मैं कहती हूं, मुझे भगवान ने दो बेटियां दी हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुई और मेरे घर में भी हम तीन बहनें थीं। मेरी मम्मी पर हमेशा से प्रेशर था कि बेटा होना चाहिए और उसी प्रेशर के चलते हम तीन बेटियां भी हुईं। मगर फिर मेरे पिता ने तय किया कि वे अपनी तीनों बेटियों को बेटे की तरह पालेंगे। अब जब मैं अपने घर जाती हूं और दादी को पूछती हूं कि क्या उन्हें अब भी पोते की खलिश है, तो वे कहती हैं, नहीं अब वे संतुष्ट हैं अपनी पोतियों से, तो कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ये सोच बदली है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम एक छोटे-से गांव से ताल्लुक रखते हैं।

शूटिंग के पहले दिन 17 रीटेक्स दिए

एक समय मिस शिमला रहीं रूबीना ने जब टेलिविजन की दुनिया में कदम रखा, तो वे टीवी पर हाइली पेड ऐक्ट्रेस बन गईं, मगर उन्हें भी सेल्फ डाउट्स से गुजरना पड़ा है। वे कहती हैं कि वे अब भी सेल्फ डाउट्स का सामना करती हैं। उन्हीं के शब्दों में, 'अपनी टीनएज में सेल्फ डाउट था कि थोड़ी-सी छोटी हूं, थोड़ी-सी मोटी हूं, शायद रोल्स न मिलें। एक डायरेक्टर ने तो मुंह पर कह दिया था कि आपका चेहरा काफी नेगेटिव है, तो आपको रोल नहीं मिलेंगे। पहले शो में तो अभिनय आता ही नहीं था। शूटिंग के पहले दिन 17 रीटेक्स दिए थे। डायरेक्टर ने पीछे से चिल्ला कर कहा, 'ये सेब की पेटी जो हिमाचल से लाए हो, हिमाचल वापिस भेज दो।' मगर फिर अपने सेल्फ डाउट्स की जर्नी को मैंने एक सक्सेज स्टोरी में तब्दील किया।

चेहरे की झुर्रियां, बढ़ा हुआ वजन, सेल्फ डाउट मदरहुड में रूबीना के लिए सेल्फ वर्थ बहुत मुश्किल रहा। वे कहती हैं, 'हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि आप आखिरी बार कब रोईं, तो मैंने कहा, 'चार दिन पहले' क्योंकि अभी डेढ़ -दो महीने पहले ही मैं अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन से उबरी हूं। उस डिप्रेशन के बारे में आपको कोई नहीं बताता। इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हमें ये कह कर चुप कराया जाता है, 'डोंट बी अ वोक'(दिखावे की प्रगतिशील मत बनो) मगर ये वॉकिज़्म नहीं है। एक साइकॉलजिकल अंधियारा होता है। मैं पूरी तरह से बदल गई थी। सूखा चेहरा, रूखे बाल, बढ़ा हुआ वजन, चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थीं। सुबह उठकर आईना देखने का मन नहीं करता था। कभी बिलकुल खाने का मन नहीं करता, तो कभी सिर्फ स्ट्रेस ईटिंग किया करती थी।'

बच्चे की पैदाइश के बाद मां का नया जन्म होता है

रूबीना बताती हैं, 'मैं तो अपने बच्चों के लिए सिब्लिंग्स इसलिए चाहती थी कि मेरे बच्चे आपस में दोस्त हों। हम तीन बहनें हैं और एक उम्र मैंने कर समझ में आया कि बहनों से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। ट्विंस मॉम के रूप में मेरी अपनी खुद की एक जर्नी रही है, तो यही वजह है कि मैं शो द वार्ड से जुड़ी।' अपने शो के बारे में वे कहती हैं, 'यह एक ऐसी कम्युनिटी है जहां नई मांएं और गर्भवती महिलाएं 10 दिनों तक साथ रहती हैं। हमने यह प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, 'मां बनना कौन-सी बड़ी बात है?' लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी बातों में से एक है। एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसके साथ उसका खुद का भी नया जन्म होता है। हमारे शो में 10 महिलाएं हैं जो अलग-अलग ट्राइमेस्टर में हैं। वे अपने अनुभव, डर, भावनाएं, मूड स्विंग्स और पूरी यात्रा को एक-दूसरे के साथ साझा करती हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हमने पहले कभी खुलकर बात नहीं की।'

पीएम मोदी की दमण यात्रा पर विभिन्न पंचायतों में सरपंचों एवं जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित

असली आज़ादी न्यूज नेटवर्क, दमण 02 जून। पीएम मोदी की 5 जून को होने वाली दमण यात्रा प्रदेशवासियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। दमण जिले की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों एवं जिला पंचायत सदस्यों द्वारा आज जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर जनता को पीएम मोदी की प्रस्तावित यात्रा एवं प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी दी गई। घेलवाड ग्राम पंचायत सरपंच हिताक्षी पटेल और जिला पंचायत सदस्य अशोक पटेल, कडैया सरपंच शंकर पटेल और जिला पंचायत सदस्य हर्षल पटेल, दुनेठा ग्राम पंचायत सरपंच आशा पटेल, भेंसलोर ग्राम पंचायत सरपंच सविता पटेल, वरकुंड ग्राम पंचायत सरपंच विजय पटेल और जिला पंचायत सदस्य सुनिता हलपति, सोमनाथ सरपंच वर्षिका पटेल और जिला पंचायत उपप्रमुख रीना पटेल, कचीगाम सरपंच फाल्गुनी पटेल और जिला पंचायत सदस्य हंसाबेन धोडी सहित के जनप्रतिनिधियों ने जनता के साथ जनसंवाद में कार्यक्रम की रूपरेखा सहित दमण में हुए आमूल परिवर्तन सहित की जानकारी देते हुए बडी संख्या में 5 जून को उपस्थित रहने के लिए विधिवत आमंत्रण दिया।

स्वामी: मारुतिनंदन पब्लिक, संपादक, प्रकाशक व मुद्रक विजय जगदीशचंद्र भट्ट द्वारा गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल, नानी दमण - 396210 से प्रकाशित तथा असली आजादी प्रेस गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल नानी दमण - 396210 से मुद्रित।
(समाचारों के चयन के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत संपादक की होगी। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दमण न्यायालय के अधीन होगा।)